



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122020-223876
CG-DL-E-23122020-223876

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942

No. 364]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/PAUSHA 1, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

मामला सं. एसएसआर-13/2019

विषय : दक्षिण अफ्रीका के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित “फेनोल” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की निर्णायक समीक्षा।

क. पृष्ठभूमि

फा. सं. 7/25/2019-डीजीटीआर.—

1. समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) को मै० दीपक फेनोलिक्स लि., मै. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक्स कैमिकल्स लि. और मै. एसआई ग्रुप इंडिया प्रा. लि. (जिन्हें यहाँ आगे “आवेदक” भी कहा गया है) से 13 नवंबर, 2019 को एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें दक्षिण अफ्रीका (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित से “फेनोल” (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद”, “पीयूसी” कहा गया है) के आयातों पर अधिनियम और

नियमावली के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लगाने के लिए निर्णायक समीक्षा (एस एस आर) जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 14/4/2002-डीजीएडी दिनांक 15 फरवरी, 2002 द्वारा यूरोपीय संघ (ईयू), सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनोल के आयातों से संबंधित मूल जांच की शुरुआत की थी। प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 14/4/2002-डीजीएडी दिनांक 24 जून, 2002 द्वारा अंतिम एडीडी की सिफारिश करते हुए प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए थे। अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/4/2002-डीजीएडी दिनांक 13 फरवरी, 2003 द्वारा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए थे जिनमें ईयू, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 47/2002-सीमा शुल्क दिनांक 24 मार्च, 2003 द्वारा निश्चयात्मक एडीडी लगाया गया था।
3. मध्यावधि समीक्षा (एम टी आर) जांच की गई थी और प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 15/4/2006-डीजीएडी के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए गए थे जिनमें शुल्क स्वरूप में बदलाव करके शुल्क की नियत राशि को लागू करने के द्वारा ईयू, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के मूल के संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निश्चयात्मक एडीडी जारी रखने की सिफारिश की गई। राजस्व विभाग ने अधिसूचना 98/2007-सीमा शुल्क 31 अगस्त, 2007 द्वारा संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक एडीडी लगाया गया था।
4. पहली एस एस आर जांच 10 अगस्त, 2007 को शुरू की गई प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 15/9/2007-डीजीएडी दिनांक 4 अगस्त, 2008 द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए जिनमें ईयू व सिंगापुर के संबद्ध वस्तु के आयातों पर समान एडीडी और दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध वस्तु के आयातों पर संशोधित निश्चयात्मक एडीडी जारी रखने की सिफारिश की गई। प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 114/2008-सीमा शुल्क दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 के माध्यम से निश्चयात्मक एडीडी लगाया गया था।
5. दूसरा एम टी आर प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 15/16/2011-डीजीएडी दिनांक 8 दिसंबर, 2011 के माध्यम से सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध फेनोल के आयातों के संबंध में शुरू की गई थी दूसरी एम टी आर जांच में अंतिम जांच परिणाम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 15/16/2011-डीजीएडी दिनांक 6 फरवरी, 2013 के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे जिनमें दक्षिण अफ्रीका के आयातों के संबंध में एडीडी को जारी रखने और ईयू तथा सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के आयातों पर शुल्क समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राजस्व विभाग ने अधिसूचना 10/2013-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 3 मई, 2013 द्वारा दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध वस्तु के आयातों पर एडीडी लागू रखने और ईयू तथा सिंगापुर से एडीडी समाप्त करने का आदेश जारी किया।
6. दूसरी एस एस आर जांच में तत्पश्चात प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश अधिसूचना संख्या 15/21/2013-डीजीएडी दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के माध्यम से की थी और इसे अधिसूचना 32/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 जुलाई, 2015 द्वारा आगे पांच वर्ष के लिए बढ़ाया गया और पुनः अधिसूचना संख्या 18/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 9 जुलाई, 2020 द्वारा इसे 9 जनवरी, 2021 तक बढ़ाया गया।
7. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार एडीडी को यदि पहले न हटाया जाए तो उन्हें लागू करने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर ये निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या एडीडी के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा, नियमावली के नियम 23 (1ख) में निम्नानुसार व्यवस्था है:

“इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्षात्कृत अनुरोध के आधार पर उस अवधि से पहले, उस अवधि की समाप्ति से तर्कसंगत अवधि के भीतर एक समीक्षा द्वारा इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि उक्त पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।”

8. उपर्युक्त के अनुसार प्राधिकारी के लिए डी आई द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्षांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या एडीडी की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
9. आवेदकों ने संयुक्त रूप से दिनांक 13 नवंबर, 2019 को एक आवेदन दायर किया है जिसमें पहले लागू एडीडी के एस एस आर शुरुआत करने और दक्षिण अफ्रीका से फेनोल के आयात हेतु एडीडी जारी रखने का अनुरोध किया गया है। यह अनुरोध इस कारण आधारित है कि उपाय की समाप्ति से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति को जारी रहने की संभावना है।
10. घरेलू उद्योग की ओर से पाटन और क्षति की संभावना के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य सहित विधिवत रूप से साक्षांकित आवेदन के मद्देनजर और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/25/2019-डीजीटीआर दिनांक 27 दिसंबर, 2019 के माध्यम से एस एस आर जांच की शुरुआत की ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू एडीडी को जारी रखने की समीक्षा की जा सके और यह जांच की जा सके कि क्या उक्त एडीडी की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
11. वर्तमान समीक्षा के दायरे में उस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/21/2013-डीजीएडी दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के सभी पहलू शामिल हैं जिसमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर एडीडी लागू करने की सिफारिश की गई थी।

ख. प्रक्रिया

12. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :-
 - i. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना संख्या 7/25/2019-डीजीटीआर 27 दिसंबर, 2019 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की।
 - ii. दिनांक 27 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना की एक प्रति प्राधिकारी द्वारा संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात निर्यातकों, भारत में संबद्ध देश के दूतावास के जरिए उनकी सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षों को नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया।
 - iii. प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार को उनके दूतावास के जरिए और अन्य हितबद्ध पक्षकार को उनके लिखित अनुरोध पर आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति उपलब्ध करायी। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में रखी गई और अनुरोध करने पर हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करायी गई।
 - iv. दक्षिण अफ्रीका के दूतावास, नई दिल्ली ने जांच शुरुआत अधिसूचना में प्रत्युत्तर में विधिक अनुरोध किए।
 - v. प्राधिकारी ने पाटनरोधी जांच की शुरुआत वाली अधिसूचना दिनांक 27 दिसंबर, 2019 की एक प्रति संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को भेजी थी और जांच शुरुआत अधिसूचना में विहित समय-सीमा या बढ़ायी गई समय-सीमा के भीतर नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार विहित ढंग और प्रपत्र में लिखित में प्रश्नावली का उत्तर देने का अवसर प्रदान किया। निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रतियां संबद्ध देश के दूतावास को भी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ भेजी गई थी और उनसे संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था।
 - vi. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर उनके उत्तर तथा अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षों हेतु समय-सीमा बढ़ायी थी। दिनांक 3 फरवरी, 2020 के पत्र द्वारा समय-सीमा 22 फरवरी, 2020 तक बढ़ायी गई थी।
 - vii. प्राधिकारी ने निम्नलिखित ज्ञात उत्पादक/निर्यातक को अधिसूचना की प्रति भेजी थी
क. मै० मेरीसोल आरएसए (पीटीवाई) लि० 2 स्टर्डी एवे, रोजबैंक सैंडटॉन 2196, दक्षिण अफ्रीका

- viii. संबद्ध जांच की शुरूआत के उत्तर में मै० ससोल दक्षिण अफ्रीका (पीटीवाई) लि० ने प्रश्नावली का उत्तर देने और अनुरोध करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया तथापि, निर्यातक द्वारा प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया गया।
- ix. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी :
- क. मै० एक्रोन इंटरप्राइजेस;
- ख. मै० ब्लीच मार्केटिंग प्रा० लि०;
- ग. मै० सी.जे. शाह एंड कंपनी;
- घ. मै० सेंट्रम मेटालिक्स प्रा० लि०;
- ङ. मै० फार्मसन फार्मास्यूटिकल गुजरात लि०;
- च. मै० हरेश कुमार एंड कंपनी;
- छ. मै० हाई पोलिमेर लैब्स लि०;
- ज. मै० इंडिया ग्लाइकोल्स लि०;
- झ. कैलाश पोलिमर्स
- ञ. मै० कांतीलाल मणिलाल एंड कं० प्रा० लि०;
- ट. मै० कारमेन इंटरनेशनल (प्रा०) लि०;
- ठ. मै० खेतान ब्रादर्स;
- ड. मै० कृष्णा आन्टीऑक्सीडेंट प्रा० लि०;
- ढ. मै० कुंदन राइस मिल्स लि०;
- ण. मेघदेव इंटरप्राइजेस,
- त. मै० नायकनवारे केमिकल्स लि०;
- थ. मै० नेशनल प्लाइवुड इंडस्ट्रीज लि०;
- द. मै० एन जी पी इंडस्ट्रीज लि०;
- ध. पारस डाइज एंड केमिकल्स,
- न. मै० पी सी एल आयल एंड इंडस्ट्रीज;
- प. मै० रेम्बो कलर्स एंड केमिकल्स;
- फ. मै० रेसिन एंड प्लास्टिक लि०;
- ब. मै० सतगुरु इंटरनेशनल;
- भ. मै० सनकमल इंटरप्राइजेस;
- म. मै० शुभम डाइज एंड केमिकल्स लि०;
- य. मै० सिंह प्लास्टिसीजर्स एंड रेसिन (आई) लि०;
- कक. मै० टोरेट फार्मास्यूटिकल्स लि०;
- खख. मै० यूनाइटेड फॉस्फोरस लि०;
- गग. मै० वंडर लैमिनेट प्रा० लि०;

- x. उपर्युक्त के उत्तर में मै० अग्रवाल केमिकल्स, आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दिया और अनुरोध किए।
- xi. निम्नलिखित पक्षकारों ने जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण किया/कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किए।
 - क. मै० सेंट प्लाई;
 - ख. मै० एक्जिमकार्प इंडिया प्रा० लि०;
 - ग. मै० अतुल लि०;
 - घ. मै० फेडरल ऑफ इंडियन प्लाईवुड एंड पैनेल इंडस्ट्री;
 - ड. मै० इंडियन लैमिनेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन;
- xii. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2019 (6 महीने) की है और क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 और पी ओ आई की है।
- xiii. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) और प्रणाली तथा आंकड़ा प्रबंध महानिदेशालय (डी जी एस) से जांच अवधि तथा जांचवार अवधि तथा पूर्ववर्ती आयात के सौदावार आंकड़े प्राप्त हुए थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और मूल्य के परिकलन हेतु डीजीसीआई एंड एस तथा डी जी एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- xiv. आवेदकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक सीमा तक सत्यापन किया गया था।
- xv. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के अगोपनीय अंश को एक सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखा था।
- xvi. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत तथा क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) ज्ञात करने हेतु नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर संभव सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम एडीडी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 18 मई, 2020 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर दिया। इसके अलावा, आटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदलने के मद्देनजर 14 अगस्त, 2020 को दूसरी मौखिक सुनवाई हुई थी जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत नहीं किए उनसे मौखिक रूप में प्रस्तुत विचारों को लिखित रूप में तथा खंडन अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
- xviii. इस जांच प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, दिए गए तर्कों और विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर साक्ष्य के साथ समर्थित सीमा तक और वर्तमान जांच में संगत समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- xix. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना की सत्यता को स्वयं को संतुष्ट किया तो संभव सीमा तक इस जांच परिणाम का आधार बनाती है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का संगत, व्यवहार्य और आवश्यक सीमा तक सत्यापन किया।
- xx. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के

समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

- xxi. ऐसे निर्यातक, विदेश उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया या इस जांच से संगत सूचना नहीं दी उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है। जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम में रिकार्ड किया है।
- xxii. नियमावली के नियम 16 के अनुसार जांच के अनिवार्य तथ्यों को 23 नवंबर, 2020 के प्रकटन विवरण के जरिए या हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों को प्राधिकारी द्वारा संगत समझे जाने पर इन जांच परिणामों में शामिल किया गया है।
- xxiii. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xxiv. पी ओ आई के दौरान प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई औसत विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 70.73 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का दायरा और समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

13. पी यू सी के दायरे और समान वस्तु के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- i. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद फेनोल है
- ii. पी यू सी को प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के अंतिम जांच परिणाम में परिवर्तित किया गया था। चूंकि वर्तमान जांच निष्कर्षक समीक्षा जांच है, इसलिए पी यू सी पूर्व में हुई जांच में परिभाषित वस्तु के समान रहेगा। इसके अलावा, इस अवधि में कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं। अतः आवेदकों ने पी यू सी के संबंध में पूर्ववर्ती जांच का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है।
- iii. इसके अलावा, वर्तमान आवेदन एडीडी को जारी रखने के लिए एस एस आर जांच हुई है। समान वस्तु के मद्देनजर प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में भी जांच की गई है। अतः आवेदकों ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देश से आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद से समान वस्तु है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

14. पी यू सी और समान वस्तु के संबंध में निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. मूल जांच, पूर्ववर्ती एस एस आर तथा वर्तमान एस एस आर में परिभाषित पी यू सी फेनोल है। पूर्ववर्ती जांच में पी यू सी को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था।

“ विचाराधीन उत्पाद सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ के मूल का अथवा वहां से निर्यातित फेनोल है। फेनोल एक मूल कार्बनिक रसायन है जिसे सामान्यतः सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय-29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इस उत्पाद को दो रूपों अर्थात् बल्क और पैकड में बेचा जाता है। बल्क बिक्रियाँ आम तौर पर खुले रूप में होती हैं जबकि पैकड पारेषण काफी छोटे कंटेनर भार में हो सकते हैं और उन्हें सामान्यतः ड्रम में पैक किया जाता है। फेनोल का प्रयोग फेनाल फार्मोल्डीहाइड रेजिंस, लेमिनेट, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, बिसफेनोल-ए, एल्काइल फेनोल्स, भेषजों, डाईफेनाइल ऑक्साइड आदि में किया जाता है इस उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 2907.11 और भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार 2707.60 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि,

सीमा शुल्क और आईटीसी एचएस वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है”।

16. समान वस्तु के संबंध में के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:- “समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;
17. “समान वस्तु” शब्द की उक्त परिभाषा से यह नोट किया जाता है कि समान वस्तु जांच के अधीन वस्तु या हर तरह से समानुरूप होनी चाहिए। समान वस्तु शब्द के दायरे में ऐसे सभी वस्तुएं भी शामिल हैं, जिनमें हर तरह से समान या समानुरूप वस्तु के अभाव में जांच के अधीन वस्तु से मिलती-जुलती विशेषताएं हों।
18. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है। इसके मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है।
19. किसी भी आयातक तथा उपभोक्ता निर्यातक घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने पी यू सी और समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठायी है। उपर्युक्त के मद्देनजर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना और रिकार्ड में उपलब्ध सूचना, वर्तमान समीक्षा जांच में पी यू सी के दायरे को मूल जांच में दायरे के समान माने जाने का आधार है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

20. घरेलू उद्योग की स्थिति और उसके दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-
 - i. आवेदकों अर्थात् मै० दीपक फेनोलिक्स लि०, मै० हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि० और मै० एस आई ग्रुप इंडिया प्रा० लि० का संबद्ध वस्तु का उत्पादन भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत बनता है।
 - ii. आवेदक न तो संबद्ध देश से किसी निर्यातक से संबंधित है और न ही भारत में किसी आयातक से संबंधित है।
 - iii. एस आई ग्रुप द्वारा किए गए आयात शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत हैं और भारत में उत्पादन और मान की दृष्टि से उनकी मात्रा मामूली है।
 - iv. घरेलू उद्योग ने पी ओ आई में दक्षिण अफ्रीका से पाटन का आरोप लगाया है और इसलिए पी ओ आई के दौरान केवल दक्षिण अफ्रीका से आयात संगत है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. घरेलू उद्योग की स्थिति और दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-
 - i. मै० एस आई ग्रुप इंडिया प्रा० लि० को घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पी ओ आई के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात किया है। यह दक्षिण अफ्रीका से आयातों का 50 प्रतिशत हो सकता है। अतः यदि आयात अधिक है तो मै० एस आई ग्रुप को बाहर किया जाना चाहिए।
 - ii. तीन घरेलू उत्पादकों ने केवल संबद्ध देश के संबंध में उत्तर दिए हैं और अन्य देशों से आयात के लिए कोई उत्तर नहीं दिए हैं। जबकि आवेदन प्रपत्र के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा आयात की घोषणा संबद्ध देश सहित सभी देशों के लिए पी ओ आई तथा पिछले तीन वर्षों हेतु स्पष्ट रूप से आवश्यक की जानी चाहिए।

- iii. मै० दीपक फेनोलिक्स लि० न तो स्थापित उत्पादक हैं और न ही मूल जांच घरेलू उद्योग का हिस्सा था। मै० दीपक फेनोलिक्स लि० ऐसी श्रेणी में आते हैं जहां क्षति का आकलन भारत में किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा उत्पन्न करने के संबंध में किया जाता है। नियमावली में स्थापित घरेलू उद्योग को ऐसे घरेलू उद्योग से जोड़ने की अनुमति नहीं है जो स्थापना में वास्तविक बाधा की समस्या से ग्रस्त हो।
- iv. चूंकि मै० दीपक फेनोलिक्स लि० पूरी क्षति अवधि में उपस्थित नहीं है, इसलिए आकलन त्रुटिपूर्ण हैं और एक समान प्रकृति का नहीं है। कार्य निष्पादन नए चालू प्रचालन तथा स्टार्ट अप लागत में मात्रा संबंधी मुद्दों से ग्रस्त है जिसे समायोजित करना अपेक्षित है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

23. वर्तमान एस एस आर आवेदन मै० एस आई ग्रुप इंडिया प्रा० लि०, मै० हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि० और मै० दीपक फेनोलिक्स लि० द्वारा दायर किया गया है। भारत में पी यू सी का कोई अन्य उत्पादक नहीं है और आवेदकों का भारत में घरेलू उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है।
24. आवेदकों ने बताया है कि वे संबद्ध वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा, मै० हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि० और मै० दीपक फेनोलिक्स लि० द्वारा भारत में उत्पाद का दक्षिण अफ्रीका से कथित पाटित वस्तु का कोई उत्पाद नहीं हुआ है।
25. यह नोट किया जाता है कि पी ओ आई के दौरान मै० एस आई ग्रुप इंडिया प्रा० लि० द्वारा किया गया आयात समग्र मात्रा (650 मी. टन) और कंपनी के उत्पादन की दृष्टि से (3.5 प्रतिशत), कुल आयात (0.8 प्रतिशत) और कुल भारतीय उत्पादन (3.9 प्रतिशत) तथा मांग (0.3 प्रतिशत) की दृष्टि से काफी कम हैं। इसके अलावा, आयात शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत किए गए थे। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि मै० एस आई ग्रुप इंडिया प्रा० लि० ए डी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं।
26. अन्य हितबद्ध पक्षों के इस तर्क के संबंध में कि मै० दीपक फेनोलिक्स लि० एक स्थापित उत्पादक नहीं है क्योंकि वह वास्तविक मंदी से प्रभावित हुए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै० दीपक फेनोलिक्स लि० ने नवंबर, 2018 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था और पहले ही 96 प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त कर लिया था तथा इसलिए उन्होंने भारत में संबद्ध वस्तु के अग्रणी उत्पादक के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया था। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि घरेलू उद्योग का दायरा निम्न के संबंध में स्थापित होना चाहिए (क) जांच अवधि में और (ख) उस अवधि के दौरान पात्र घरेलू उत्पादकों के समान वस्तु के उत्पाद में प्राधिकारी मानते हैं कि मै० दीपक फेनोलिक्स लि० घरेलू उद्योग एक हिस्सा है।
27. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मानदंडों को पूरा सकता है।

ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए अनुरोध

28. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- i. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 के सख्त अनुपालन में समस्त सूचना प्रस्तुत की है। कंपनी-वार ब्यौरे और आवेदकों द्वारा किए गए आयातों के ब्यौरे व्यापार स्वामित्व की सूचना है जो सारांश योग्य नहीं है।

- ii. प्राधिकारी की व्यापार सूचना संख्या 7/2018 दिनांक 15 मार्च, 2018 में केवल डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों की मूल प्रति को जांचकर्ता अधिकारी से घोषणा/वचनबद्धता लेने के बाद ही हितबद्ध पक्षों को दिए जाना ही अधिदेशित है।
- iii. समुद्री मालभाड़ा समायोजन के साक्ष्य आवेदन में दिए गए हैं। अन्य समायोजनों के संबंध में उन्हें प्राधिकारी की स्थापित परिपाटी के अनुसार किया गया है।
- iv. मात्रा संबंधी मापदंडों की सूचना व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 के सख्त अनुपालन में अगोपनीय रूप में दी गई है, जो यह देखते हुए दो उत्पादकों हेतु लागू है कि क्षति अवधि में नवंबर, 2018 तक घरेलू उद्योग में केवल दो उत्पादक थे।
- v. खरीद नीति, बिक्री नीति, लेखांकन नीति, लागत लेखांकन नीति, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया और परीक्षण व्यापार स्वामित्व की सूचना और उसका सारांशीकरण संभव नहीं है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए अनुरोध

29. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. घरेलू उद्योग द्वारा चयनित डीजीसीआई एंड एस की एक्सेल फाइल की साफ्ट कॉपी नहीं दी गई है।
- ii. मै० एस आई ग्रुप इंडिया प्रा० लि० द्वारा कंपनी-वार सूचना और आयातों के ब्यौरे घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय दावा किए हैं।
- iii. आवेदकों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट नहीं दी गई हैं केवल वेबसाइट के लिंक बताए गए हैं।
- iv. मात्रा, आंकड़े और लाभ प्रतिशत में आवेदकों द्वारा गोपनीय होने का दावा किए गए हैं।
- v. पाटनरोधी करार और नियमावली के उल्लंघन में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री जैसे आर्थिक मापदंडों केवल सारांशीकृत आंकड़े लिए गए हैं। इसी उत्पाद की पूर्ववर्ती जांच से सूचना में काफी अंतर है।
- vi. खरीद नीति, बिक्री नीति, लेखांकन नीति, लागत लेखांकन नीति, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया और परीक्षण को भी गोपनीय माना गया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. जांच की प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता के संबंध में आवेदकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षों के विभिन्न अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक जांच की गई है।
31. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल के जरिए निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखा था।
32. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है :-

“ गोपनीय सूचना’ (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा। आयातों, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन, मापदंडों और क्षति मापदंडों की सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध करायी गई है। परिपाटी के अनुसार व्यापार संवेदी सूचना को गोपनीय रखा गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध किसी सूचना को गोपनीय नहीं माना जा सकता है।
34. डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के प्रकटन के संबंध में प्राधिकारी की व्यापार सूचना संख्या 7/2018 दिनांक 15 मार्च, 2018 में घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों हेतु डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया विहित है। इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकारों की व्यापार सूचना के अनुसार डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों तक पहुंचा है और अपने हितों की रक्षा वे कर सकते हैं।

च. विविध अनुरोध

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

35. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :-

- i. किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है अतः नियम 6(8) के अनुसार निर्यातकों को असहयोगी माना जाना चाहिए और प्राधिकारी को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।
- ii. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विहित समय-सीमा के भीतर कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।
- iii. मै० अग्रवाल केमिकल भारत में पाटित जांच के अधीन वस्तु के आयातक नहीं हैं क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से पी यू सी का आयात नहीं किया है।
- iv. फेडरेशन ऑफ इंडियन प्लाईवुड एंड पैनल इंडस्ट्री असहयोगी हैं क्योंकि एसोसिएशन के अधीन किसी भी प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इसके अलावा, स्वयं एसोसिएशन ने भी विहित समय-सीमा के भीतर कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।
- v. मै० सेंट प्लाई ने प्राधिकारी द्वारा जारी विहित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। पक्षकार ने केवल हितबद्ध पक्षकारों के विरोध में अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। पक्षकार को वर्तमान जांच में असहयोगी माना जाना चाहिए।
- vi. मै० ससोल लि० को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने न तो विहित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी के समक्ष स्वयं को पंजीकृत किया है न ही व्यापार सूचना संख्या 11/2018 दिनांक 10 सितंबर, 2018 द्वारा अधिदेशित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।
- vii. दक्षिण अफ्रीकी उत्पादक ने कोरोना वायरस की आड़ में असहयोग को उचित ठहराने का प्रयास किया है। यह जांच दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस समस्या के शुरू होने से काफी पहले दिसंबर, 2019 में शुरू हुई थी। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने 25 मार्च, 2020 तक कोई लाकडाउन घोषित नहीं किया था।
- viii. हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए 2 हफ्तों का अतिरिक्त समय दिया गया। घरेलू उद्योग अतिरिक्त प्रदत्त समय के बावजूद प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने में प्रतिवादी निर्यातकों की कठिनाई को नहीं समझ पा रहा है।
- ix. कोविड 19 पी यू सी के पाटन की अनुमति देने का बहाना नहीं हो सकता है।

- x. जहां बल्क सौदों का उल्लेख है, वहां उन्हें बल्क माना गया है। आयात सौदों में जहां बल्क का उल्लेख नहीं है, वहां उन्हें मात्राओं के अनुसार बल्क और पैकड के बीच अलग-अलग किया गया है। यदि मात्रा 100 मी. टन से अधिक है तो बल्क माना गया है। पी ओ आई के दौरान असामान्य कीमत की वजह से 110 किलोग्राम के केवल एक सौदे को बाहर रखा गया है। यह मात्रा कीमत प्रभाव पर असर डालने के लिए बहुत कम या लगभग शून्य है।
- xi. वह अवधि जिसके लिए शुल्क लागू है। यह निर्धारित करने हेतु संगत नहीं है कि क्या एडीडी का आगे विस्तार करना अपेक्षित है। एक मात्र संगत विचार धारा 9क (5) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तें हैं।
- xii. प्राधिकारी ने इस कारणवश 10 वर्ष के बाद की अवधि के लिए शुल्क को जारी रखा है कि शुल्क की समामि की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। वर्तमान मामले के तथ्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संदर्भित मामलों के बिल्कुल विपरीत है।
- xiii. प्राधिकारी द्वारा विचारित पी ओ आई तथ्य और मामले की परिस्थितियों के कारण उचित है। पी यू सी की आयात कीमतें पी ओ आई के दौरान काफी कम हुई थीं जबकि कच्चे सामग्री की कीमतों में कोई संगत गिरावट नहीं हुई।
- xiv. चीन द्वारा एडीडी लागू होने से कीमतों में काफी अधिक गिरावट हुई है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

36. निम्नलिखित विविध अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए हैं :-

- i. पी ओ आई सामान्यतः 12 महीने की होती है। 6 महीने की पी ओ आई मानने के लिए कोई आपवादित परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं। पहली बार कोई एस एस आर जांच 6 महीने की पी ओ आई में हो रही है। घरेलू उद्योग ने 2019-20 की पहली दो तिमाही में लाभप्रदता कम होने के परिणामस्वरूप क्षति दर्शाने के लिए 6 महीने की कम पी ओ आई को चुना और उसका प्रस्ताव किया है। फेनोल कच्चे पेट्रो और प्राकृतिक गैस की एक व्युत्पत्ति है और इसे उसी पैमाने से नहीं मापा जाना चाहिए जो अन्य औद्योगिक उत्पादों पर लागू हैं। फेनोल की बिक्रियां दैनिक आधार पर लागतों और बिक्री कीमतों में निरंतर उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती है। इस प्रकार, सटीक और वस्तुनिष्ठ आकलन के लिए कम से कम 12 महीने की अवधि अनिवार्य है और 6 महीने की पी ओ आई बिल्कुल अपर्याप्त है। व्यापार सूचना संख्या 2/1017 दिनांक 12 दिसंबर, 2017 का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि उसमें कम से कम एक वर्ष की पी ओ आई अधिदेशित है।
- ii. चीन में फेनोल पर एडीडी लागू होना आपवादित परिस्थिति नहीं है। दक्षिण अफ्रीका संबद्ध देश नहीं था और न ही उसके निर्यात चीन को उसके निर्यात अधिक थे। सितंबर, 2019 से पहले चीन द्वारा केवल अनंतिम शुल्क लगाए गए थे। अंतिम शुल्क लागू होने तक अंतरिम शुल्क का कोई अर्थ नहीं होता है। आयात अनंतिम शुल्क के कारण पी ओ आई में केवल चार महीनों के लिए हुए थे। पी ओ आई के लिए आपवादित परिस्थितियों को उचित ठहराने हेतु यह पर्याप्त नहीं है।
- iii. आयात कीमतों में गिरावट कच्ची सामग्री की कीमत में अस्थिरता के कारण ही हुई है।
- iv. प्राधिकारी ने पहले यह सही माना है कि 10 वर्ष से अधिक एडीडी को केवल विशेष मामलों में लागू किया जाता है। एडीडी को जारी रखने के लिए कोई विशेष परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं।
- v. चूंकि आयात शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत हैं, इसलिए वर्तमान मामले में एडीडी को बढ़ाना अपेक्षित नहीं है।
- vi. मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई) जीडीपी का 50 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं और दो तिहाई औपचारिक रोजगार देते हैं। ये भारत में फेनोल का सबसे बड़ा प्रयोक्ता आधार हैं। एडीडी को जारी रखने से एमएसएमई बुरी तरह से प्रभावित होंगे। एडीडी को लगाना अनुपयोगी होगा क्योंकि इससे विकास बाधित होगा। कोविड-19 ने पहले ही विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को क्षति पहुंचायी है और वैश्विक मंदी के दौरान पाटनरोधी उपाय अनावश्यक हैं।

- vii. प्रश्नावली का उत्तर देने की समय-सीमा नहीं बढ़ाना, मनमाना और अनुचित है। इसे प्राधिकारी की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए था। विशेष रूप से, क्योंकि ससोल दक्षिण अफ्रीका से उत्पादक-निर्यातक है।
- viii. कोविड-19 महामारी जो दिसंबर, 2019 में शुरू हुई, को देखते हुए सूचना प्रदान करने की पक्षकारों की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई थी।
- ix. बल्क और पैकड आयातों को अलग करना मनमाना है जब सौदे को बल्क या पैकड में अलग नहीं किया जा सकता है, तो कीमत विश्लेषण हेतु ऐसे सौदों का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दक्षिण अफ्रीका से उच्च कीमत वाले सौदों को यह कह कर बाहर कर दिया है कि वे असामान्य हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह इन आयात सौदों पर विचार करें।
- x. उच्चतर कीमत वाली इकाइयों को असामान्य बताकर बाहर कर दिया है। ऐसे कार्य शून्य अनुमान माने जाएंगे जिनकी अनुमति नहीं है।
- xi. ससोल वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ स्पष्टतः एक हितबद्ध पक्षकार है और सुनवाई में भाग लेने तथा प्राधिकारी को अपने विचार बताने का उसे पूरा कानूनी अधिकार है। चाहें उसने प्रश्नावली का उत्तर दिया हो अथवा नहीं।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 37. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के सभी तर्कों और खंडनों को नोट किया है और किए गए अनुरोधों के सभी पहलुओं की जांच की है।
- 38. आयातक मै० अग्रवाल केमिकल्स के एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पात्रता के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ग) में निम्नानुसार व्यवस्था है-
 “(ग) “हितबद्ध पक्षकार” में शामिल हैं-
 i. भारत में पाटन के लिए जांचाधीन किसी वस्तु का कोई निर्यातक या कोई विदेशी उत्पादक या आयातक या कोई व्यापारी या ऐसी व्यापारिक एसोसिएशन जिसके अधिकांश सदस्य ऐसे किसी वस्तु के उत्पादक, निर्यातक या आयातक हों;
 ii. निर्यातक देश की सरकार ; और
 iii. भारत में समान वस्तु का कोई उत्पादक या कोई व्यापार और व्यापार एसोसिएशन जिसके अधिकांश सदस्य भारत में समान वस्तु का उत्पादन करते हों”
- 39. जैसा आयातक प्रश्नावली के उत्तर में मै० अग्रवाल केमिकल ने रिकार्ड में प्राधिकारी को बताया है कि आयातक ने संबद्ध देश से पी यू सी का कोई आयात नहीं किया है। अतः पक्षकार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयातक नहीं है। तथापि, पक्षकार ने अन्य देशों से उत्पाद का आयात किया है। प्राधिकारी ने यह देखते हुए कंपनी द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया है कि कंपनी ने यद्यपि दूसरे स्रोत से उत्पाद का आयात किया है।
- 40. 6 महीने की पी ओ आई का चयन करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि 6 महीने की पी ओ आई को अपनाना नियमावली और मामले की अपेक्षा से असंगत नहीं है। घरेलू उद्योग ने कारण बताते हुए पी ओ आई के रूप में 6 महीने पर विचार करने की जरूरत को साक्षांकित किया है कि इस अवधि के दौरान आयात कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। आवेदकों ने बताया है कि जांच अवधि तय करने का उद्देश्य ऐसी अवधि तय करना है जिसमें यह निर्धारित हो कि क्या उत्पाद पाटित कीमत पर निर्यातित हुआ या क्या उससे क्षति हुई। प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तावित पी ओ आई को घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कारण से संतुष्ट होने पर स्वीकार किया है। इसके अलावा, चूंकि वर्तमान जांच एस एस आर जांच है। इसलिए प्राधिकारी ने पी ओ आई के बाद की अवधि (अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020) की सूचना पर भी विचार किया है।
- 41. प्रश्नावली का उत्तर देने की समय-सीमा जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित थी और प्राधिकारी ने समय-सीमा दो सप्ताह हेतु बढ़ायी थी। समय की कमी के मद्देनजर आगे समय-सीमा नहीं बढ़ायी गई थी।

42. मै० ससोल दक्षिण अफ्रीका (पीटीवाई) लि०, फेडरेशन ऑफ इंडियन प्लाईवुड एंड पैनल इंडस्ट्री और मै० सेंट प्लाई के पात्रता संबंधी अनुरोध के बारे में प्राधिकारी ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा प्राधिकारी की प्रक्रिया के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को माना और स्वीकार किया है।
43. यह तर्क कि अग्रिम लाइसेंस के तहत किए गए आयात को कुल आयातों से बाहर रखना चाहिए, जांचा गया था। अग्रिम लाइसेंस/प्राधिकार धारक के पास यह विकल्प होता है कि या तो शुल्क मुक्त आधार पर निविष्टियों का आयात करे या अग्रिम रिलीज आदेश के तहत तंत्र का प्रयोग करके घरेलू स्रोतों से उनकी खरीद करे। क्षति विश्लेषण का प्रयोजन घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच और आकलन करना है। अतः शुल्क मुक्त आयात को क्षति विश्लेषण से बाहर रखना तर्कसंगत नहीं होगा। यह विचार करना उचित नहीं होगा कि अग्रिम लाइसेंस के तहत हुए आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।
44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से पी यू सी के सभी आयात बल्क रूप में थे।
45. केवल असामान्य रूप से निर्धारित कीमत वाले पी यू सी को विश्लेषण के प्रयोजनार्थ शामिल नहीं किया गया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

46. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-
- घरेलू उद्योग ने दक्षिण अफ्रीका में सामान्य मूल्य का दावा बेल्जियम को उसकी निर्यात कीमत के आधार पर किया है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का वह दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
 - समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा और पत्तन व्यय के लिए निर्यात कीमत समायोजित की गई है ताकि निर्यात निवल कीमत ज्ञात की जा सके।
 - परिकलित पाटन मार्जिन न केवल अत्यधिक है, बल्कि काफी अधिक है।
 - सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु एक अधिमानी क्रम है। उच्चतम न्यायालय ने भी वाणिज्य मंत्रालय बनाम मै० हल्दोर तोप्सो मामले में यह माना है। यदि निर्यातक देश में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनीय कीमत के संबंध में स्वीकार सामग्री उपलब्ध है तो सामान्य मूल्य उसके आधार पर ही निर्धारित होगा।
 - साउथ अफ्रीकन रिवेन्यू सर्विस (एसएआरएस) दक्षिण अफ्रीकी सरकार की राजस्व सेवा (कर संग्रहण एजेंसी) है। विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने न तो यह सिद्ध किया है कि एसएआरएस के आंकड़े क्यों उचित नहीं हैं और न ही सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु कोई वैकल्पिक पद्धति बतायी है। प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार किसी आधार के बिना संबद्ध देश की सरकार के आंकड़ों पर प्रश्न उठा रहे हैं।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

47. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-
- बेल्जियम को किए गए निर्यातों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्यात करने की अनुमति नहीं है, जो कि अत्यधिक बढ़ाया गया है। प्रक्रिया के अनुसार, निर्यातक द्वारा सहयोग नहीं किए जाने के कारण घरेलू उद्योग की लागत का सामान्य मूल्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। यह तर्क कि बेल्जियम भारत के बाद सबसे बड़ा बाजार है और इसीलिए एकाएक किसी का भी मूल्य लेना उपयुक्त है। यह देखा जाना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के साथ तुलना करने के लिए बेल्जियम कैसे उपयुक्त है। अन्य देशों की कीमतों पर केवल ऐसी स्थिति में ही भरोसा किया जाना चाहिए, जब सामान्य व्यापार अवधि में अथवा अन्यथा समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो। घरेलू उद्योग से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है कि ऐसी स्थिति

- मौजूद है। अनुलग्नक-1, पैरा 7 के अनुसार एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के निर्धारण के प्रयोजन के समान मापदंड के आधार पर ही एक उपयुक्त तीसरे देश का निर्धारण किया जाना चाहिए।
- ii. घरेलू उद्योग की लागतों के आधार पर पाटन मार्जिन की गणना करने में कोई मेरिट नहीं है, क्योंकि सासोल की प्रक्रिया और कच्ची सामग्रियां पूरी तरह से अलग-अलग हैं और घरेलू उद्योग की तरह से नहीं हैं।
 - iii. कानूनन स्थायी सामान्य मूल्य न होने के कारण आवेदन को अस्वीकार किया जाना चाहिए। यदि सामान्य मूल्य अस्थायी है तो पाटन मार्जिन भी अस्थायी है।
 - iv. एस ए आर सांख्यिकी के आधार पर आई टी सी गणनाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो बिक्री का स्थान पता लगाया जा सकता और न ही उसकी शर्तों का पता चल सकता है।
 - v. समुद्री मालभाड़ा, वैश्विक मालभाड़ा दरों के लिए एल एल सी के डाटा की कोई प्रामाणिकता नहीं है और स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये एक सार्वजनिक प्राधिकरण से प्राप्त नहीं किए गए हैं और इसलिए इन्हें कानूनी रूप से स्पष्ट तथ्य नहीं माना जा सकता।
 - vi. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत समायोजनों के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए हैं। मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन और स्वदेशी परिवहन के संबंध में दावे काफी अधिक हैं और बिना किसी प्रमाणित साक्ष्य के हैं।
 - vii. चूंकि फिनोल की कीमत में दैनिक आधार पर उतार-चढ़ाव रहता है और एक बाजार से दूसरे बाजार तक अलग-अलग होती है, इसलिए एन आई पी के सामान्य मूल्य के लिए यह सिद्धांत नहीं हो सकता।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. धारा 9 (1) (ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

49. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातक को प्रश्नावली भेजी है जिसमें उन्हें निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से सूचना प्रदान करने का परामर्श दिया गया था। तथापि, संबद्ध देश से निर्यातक ने इस जांच में अपना प्रश्नावली उत्तर दाखिल न करके सहयोग नहीं किया है।

सामान्य मूल्य

50. चूंकि संबद्ध देश से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है और किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने संबद्ध देश में समान वस्तु की घरेलू कीमतों के कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं, अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के रूप में बेल्जियम को साउथ अफ्रीका से किए गए निर्यात की कीमत को अपनाकर नियम 6 (8) के अनुसार सर्वोत्तम

उपलब्ध सूचना के आधार पर सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। साउथ अफ्रीका के लिए बेल्जियम दूसरा सबसे बड़ा निर्यात का स्थान है, जबकि पहला स्थान भारत का है और भारत को निर्यातों का 5 प्रतिशत से अधिक भाग शामिल है। निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

51. चूंकि किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी ने सी आई एफ कीमत का निर्धारण करने के लिए डीजीसीआई एंड एस के आयात संबंधी आंकड़ों को अपनाया है। उपलब्ध तथ्यों के अनुसार समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा और बंदरगाह व्यय के संबंध में समोयाजनों पर विचार करके कारखाना बाह्य निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। तदनुसार, कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना की गई है और पाटन तालिका में दर्शाई गई है।

संबद्ध देश में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण

52. उपरोक्तानुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करके संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे दिया गया है। यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन अत्यधिक है।

पाटन मार्जिन तालिका

सामान्य मूल्य	यूएस डॉलर/ मी.टन	***
निर्यात कीमत	यूएस डॉलर/ मी.टन	***
पाटन मार्जिन	यूएस डॉलर/ मी.टन	***
	%	***
	रेंज	80-100

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

53. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं :
- भारत में क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में वृद्धि हुई है।
 - पाटनरोधी शुल्क के बावजूद आयात जारी रहे हैं। निरपेक्ष दृष्टि से आयात अधिक रहे हैं और जांच की अवधि में मामूली गिरावट के साथ क्षति अवधि के दौरान लगभग समान स्तर पर रहे हैं।
 - जांच की अवधि के बाद आयातों में वृद्धि हुई है (करीब 50 प्रतिशत तक) ।
 - कुल आयातों में संबद्ध देश का हिस्सा क्षति अवधि के दौरान लगभग दोगुना है। खपत के संबंध में आयातों में जांच की अवधि के उपरांत की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
 - आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा रही है।
 - आयातों से घरेलू उद्योग की काफी कम कीमत पर बिक्री हो रही है। जांच की अवधि के दौरान और क्षति अवधि के दौरान और क्षति अवधि के पश्चात क्षति मार्जिन सकारात्मक है।
 - घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है और यह कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट के कारण नहीं है। बिक्री कीमतों में गिरावट लागत में गिरावट से अधिक है, इस प्रकार इससे कीमत पर दबाव पड़ रहा है।

- viii. घरेलू उद्योग भारत में पाटित उत्पादों की मौजूदगी के कारण लाभ अर्जित करने में असमर्थ है। जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान हानियों में भी वृद्धि और बढ़ी है।
- ix. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है, क्योंकि मै० दीपक फिनोलिक्स लि० ने जांच की अवधि के दौरान अपना उत्पादन शुरू किया है। परिणामस्वरूप, घरेलू उत्पादन और बिक्रियों में भी वृद्धि हुई है।
- x. भारत में नई क्षमताओं के साथ, घरेलू उद्योग के बाजार अंश में भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयातों के बाजार अंश में भी जांच की अवधि के बाद वृद्धि हुई है।
- xi. घरेलू उद्योग के पास पूरी जांच की अवधि के दौरान इन्वेंट्री अत्यधिक रही है और इस अवधि में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- xii. निवेश पर प्रतिफल में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है और जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान भी गिरावट आई है।
- xiii. तिमाही-वार विश्लेषण में घरेलू उद्योग के निष्पादन में और भी गिरावट दर्शाई गई है। जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की प्रत्येक तिमाही में हानियों में वृद्धि हुई है।
- xiv. यह तथ्य कि भारत में खपत भारतीय उत्पादकों की क्षमताओं से अधिक है, यह अपने आप में आयातों को स्पष्ट करता है। तथापि, इससे पाटन को स्पष्ट नहीं किया जा सकता।
- xv. जांच की अवधि के लिए एन आई पी की गणना की जानी अपेक्षित है। वर्तमान मामले में जांच की अवधि कोविड-19 से प्रभावित नहीं थी और इसलिए तर्क को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
- xvi. कानून में यह एक स्थापित स्थिति है कि किसी मामले में हर प्रकार की क्षति साथ में मौजूद हो सकती है। घरेलू उद्योग ने ट्रिसियो यूरोप जीएमबीएच बनाम भारत संघ मामले का हवाला दिया है।
- xvii. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के लिए यह मान लेना काफी पूर्व कल्पना है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में 2016-17 से कोई परिवर्तन नहीं आया है। यहां तक कि मै० हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि० के सार्वजनिक बयान भी यह दर्शाएंगे कि वह अब एक रुग्ण इकाई नहीं है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

54. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि :

- i. आयात अवश्यंभावी हैं, क्योंकि घरेलू उद्योग भारत में समस्त मांग को पूरा करने में असमर्थ है। घरेलू उद्योग मांग का केवल 70 प्रतिशत ही पूरा कर सकता है।
- ii. कोविड-19 के कारण, कच्ची सामग्री की कीमतें अभी तक की कीमतों में सबसे नीचे गई है। अतः तदनुसार, एन आई पी की गणना विधिवत समायोजनों के साथ पुनः की जाए।
- iii. मात्रात्मक मापदंडों में पर्याप्त सुधार आया है और साउथ अफ्रीका से 15,000 मी. टन आयात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- iv. वर्तमान जांच में कोई भी कीमत कटौती और कोई भी कीमत ह्रास अथवा दबाव नहीं है और इसलिए कोई कीमत प्रभाव मौजूद नहीं है।
- v. घरेलू उद्योग द्वारा डब्ल्यू टी ओ के क्षेत्राधिकार की व्याख्या त्रुटिपूर्ण है और शून्यीकरण करने की अनुमति नहीं है। पैनल में कीमतों में कटौती पर बिक्री की संख्या की जांच के बारे में ही उल्लेख किया गया है और ऐसी बिक्रियों की कटौती की मात्रा का जांच के किसी अन्य रूप में उल्लेख नहीं किया गया है।
- vi. क्षति अवधि के दौरान बिक्रियों की लागत में गिरावट आई है लेकिन बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है और इसीलिए आयातों का कोई कीमत संबंधी प्रभाव नहीं है।
- vii. सभी लाभ संबंधी मापदंडों में क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त सुधार आया है और इसीलिए घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

- viii. केवल सकारात्मक कीमत कटौती की मौजूदगी होने से क्षति मार्जिन का स्वतः ही यह अर्थ नहीं हो जाता कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- ix. कीमत कटौती के मार्जिन में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है, जिसमें कम मात्रा में कीमत कटौती और मार्जिन दर्शाया गया है।
- x. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वृद्धि जांच की अवधि में कुल मांग की 15 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हुई है। अतः संबद्ध देश से आयातों के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- xi. घरेलू उद्योग को क्षति में वृद्धि के साथ कीमत में कोई हास, दबाव या कटौती होने, बिक्रियों की मात्रा में वृद्धि होने जैसे कारक क्षति नहीं दर्शाते।
- xii. प्राधिकारी के जांच परिणामों को देखते हुए मै० हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि० की वर्तमान स्थिति की पुनः जांच की जानी चाहिए। इसी प्रकार, डीजीटीआर ने पाया है कि मै० एस आई ग्रुप इंडिया प्रा० लि० पूरी क्षमता पर प्रचालन कर रहा था और उनका उत्पादन विदेशों से आयातों के कारण प्रभावित नहीं पाया गया था।
- xiii. जब से पूर्व जांच परिणाम प्रदान किए गए हैं, परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मै० दीपक फेनोलिक्स लि० के लिए, आवेदकों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी कथित क्षति अन्य पाटित आयातों के कारण क्यों नहीं थी। हो सकता है कि नए भागीदार लाभ कमा रहे हों और पुराने भागीदार प्रभावी संयंत्र और मशीनरी के कारण हानि में हों। इसके अलावा, समग्र घरेलू उद्योग के लिए क्षति निर्धारित की गई है न कि घरेलू उद्योग के अलग-अलग घटकों के लिए।
- xiv. मै० दीपक फेनोलिक्स का फिनोल एसिटोन संयंत्र घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं दिखाता। दीपक फेनोलिक्स ने नवम्बर, 2018 में अपने फिनोल संयंत्र को चालू किया है और उसके पास भारत की संस्थापित क्षमता का 72 प्रतिशत से अधिक है। अन्य दो निर्माताओं मै० हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स और एस आई ग्रुप के पास बहुत ही कम क्षमता के संयंत्र हैं और बेन्जीन तथा प्रोपाइलीन में बिना एकीकरण के ऐसे छोटे संयंत्र प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकते। इस प्रकार, दोनों छोटे भागीदारों को क्षति, यदि कोई हो, आयातों के कारण नहीं हो सकती। दीपक फेनोलिक्स ऐसी छोटी आयातों के अवधि में 100 प्रतिशत के करीब क्षमता पर संयंत्र को चलाने में समर्थ नहीं रहा है। अधिक लाभ और अधिक क्षमता उपयोग यह दर्शाता है कि दीपक फिनोलिक्स को कोई क्षति नहीं हुई है।
- xv. घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि देश में मांग 88,000 मी. टन प्रति वर्ष तक संस्थापित क्षमता से अधिक है। उनका अनुमान है कि भारत में फिनोल के लिए मांग का 1,00,000 मी. टन उत्पादों के निर्माण से आता है और इस प्रकार, उन्हें मांग आपूर्ति अंतराल से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आयात अग्रिम लाइसेंस के तहत किए जा सकते हैं, जहां कोई शुल्क लागू नहीं होगा। निर्यात के उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त 1,00,000 मी. टन फिनोल को दर्शाने की सूचना का क्या स्रोत है ? यह राष्ट्र के हित में है कि हम अधिक से अधिक स्थानीय कच्ची सामग्रियों का स्थानीय और तैयार माल का निर्यात मांग, दोनों के लिए उपयोग करे और घरेलू उद्योग के तर्क के अनुसार 1,00,000 मी. टन तक स्थानीय मांग को घटाने का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार, फिनोल की भारतीय मांग और आपूर्ति के बीच स्पष्ट अंतर है।
- xvi. प्राधिकारी अपने ही व्यापार नोटिस की उपेक्षा नहीं कर सकते और किसी भी पक्ष को कोई भावनात्मक अथवा विशेष रियायत नहीं दे सकते।
- xvii. यह आकलन करने के लिए एक कारक के रूप में कम कीमत पर बिक्री पर विचार नहीं किया जा सकता कि क्या घरेलू उद्योग पर्याप्त क्षति का सामना कर रहा है और इस पर लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क की मात्रा के प्रयोजन के लिए ही विचार किया जाना है। जहां तक पर्याप्त क्षति के निर्धारण का संबंध है, कम कीमत पर बिक्री एक असंगत कारक है,।

- xviii. स्टैंडअलोन आधार पर आयात कीमतों में गिरावट को देखना उपयुक्त नहीं है। लागतों में गिरावट को देखते हुए इसकी जांच की जानी चाहिए।
- xix. फिनोल के संबंध में व्यापार उपचारी उपाय वर्ष 1999 से जारी है। यदि पाटनरोधी शुल्क क्षति को रोकने में विफल रहे हैं तो क्षति के योगदान के लिए कथित पाटन के अलावा कोई अन्य कारक हैं।
- xx. यदि कीमतों को प्रभावित करने वाली वैश्विक मंदी के कारण क्षति हो रही है तो यह पाटन के अलावा भी एक कारक है।
- xxi. फिनोल के उत्पादन के दौरान एक सह उत्पाद तैयार किया गया है, जिसका भारत में बाजार साइज अपर्याप्त है। आवेदक लाभकारी कीमतों पर सह उत्पाद का निपटान करने में समर्थ नहीं है। सह उत्पाद का निपटान करने में अक्षमता आदेकों की क्षति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। प्राधिकारी द्वारा कोई निर्णय लेने से पूर्व इसकी भी विस्तार से जांच की जानी चाहिए।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 55. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से किए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को शामिल किया गया है।
- 56. नियमावली के नियम 11 के साथ पठित इसके अनुलग्नक- II के तहत यह प्रावधान है कि एक क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाते हैं, "पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं के लिए कीमतों पर उनके प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामस्वरूप प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए.....।"
- 57. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामस्वरूप प्रभाव के संबंध में नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iv) के तहत यह प्रावधान है कि :
"(IV) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"
- 58. नियम के तहत (क) समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में पाटित आयातों की मात्रा और कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव ; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामस्वरूप प्रभाव, दोनों की एक उद्देश्यपरक जांच के लिए प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह जांच करनी अपेक्षित है कि क्या भारत में उत्पादन अथवा खपत के निरपेक्ष संदर्भ में अथवा सापेक्ष संदर्भ में पाटित आयातों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत संबंधी प्रभाव के संदर्भ में, घरेलू उद्योग को यह जांच करनी अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों का अन्यथा दमन करने के लिए है या कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में हो गई होती। वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा और कीमत संबंधी प्रभावों और लाभप्रदता की जांच की है ताकि पाटन और क्षति, यदि कोई हो, के बीच क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच हो सके।
- 59. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के तहत यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, और 20 के प्रावधान समीक्षा के मामले में यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि उसे वर्तमान क्षति अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है, तो प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क समाप्त होने से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

60. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के संबंध में पाटन और क्षति के पहलुओं की संभावना की जांच शुरू करने से पूर्व वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच के लिए आगे कार्रवाई करते हैं। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना आवश्यक समझा गया कि भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों का महत्वपूर्ण मात्रा में दमन करने अथवा कीमत में वृद्धि में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में होती। भारत में घरेलू उद्योग पर घरेलू आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन इत्यादि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों पर नियमावली के अनुबंध- II के अनुसार विचार किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग और निर्यातकों/ आयातकों/ व्यापारियों/ प्रयोक्ताओं के, किए गए अनुरोधों को नोट किया है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करके उसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा यहां किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का स्वतः समाधान करता है।
61. मांग आपूर्ति अंतराल के तर्क के संबंध में प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि संभव मांग आपूर्ति अंतराल किसी घरेलू उद्योग को, क्षति के कारण होने वाले पाटित आयातों की समस्या के निवारण की मांग करने से वंचित करने का एक कारण नहीं हो सकता।
62. इस तर्क के संबंध में कि एन आई पी का निर्धारण, वर्तमान कच्ची सामग्री की कीमतों जो कोविड-19 की स्थिति के चलते काफी कम है, के आधार पर नहीं किया जा सकता, अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के लिए एन आई पी का निर्धारण करने की प्राधिकारी की सतत प्रथा रही है और तदनुसार, इस वर्तमान मामले में भी एन आई पी का निर्धारण किया गया है।
63. साउथ अफ्रीका से आयातों की कम मात्रा के संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
64. जहां तक लम्बी शुल्क अवधि के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कानून में यह स्पष्ट किया गया है कि समय-समय पर पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाया जा सकता है। यदि यह पाया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क समान होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
65. इस तर्क के संबंध में कि कम कीमत पर बिक्री क्षति के विश्लेषण के लिए एक मापदंड नहीं है, अतः यह नोट किया जाता है कि कानून में मापदंडों की एक संपूर्ण सूची का प्रावधान नहीं है, जिसकी क्षति विश्लेषण के लिए जांच की जा सकती है। इसके अलावा, कम कीमत पर बिक्री समग्र देश के लिए क्षति मार्जिन के अलावा कुछ भी नहीं है और इसकी जांच करने की प्राधिकारी की एक समान प्रक्रिया रही है।
66. इस तर्क के संबंध में कि मै० दीपक फिनोलिक्स लि० एसिटोन और फिनोल के कारोबार में भारी लाभ अर्जित कर रहा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में संबंधित उत्पाद के लिए विश्लेषण किया जाना चाहिए न कि समूचे क्षेत्र के लिए उपलब्ध डाटा/ सूचना के आधार पर फिनोल के लिए घरेलू उद्योग को क्षति का विश्लेषण किया गया है।
67. इसके अलावा, यह आवश्यक नहीं हो सकता कि क्षति के सभी मापदंडों में गिरावट दिखाई जाए। प्राधिकारी सभी क्षति मापदंडों पर विचार करते हैं कि उसके बाद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा नहीं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की जांच की है।

झ. मांग का आकलन

68. संबद्ध वस्तुओं की घरेलू खपत/ मांग का आकलन करने के प्रयोजन से घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री की मात्रा को भारत में कुल आयातों में शामिल किया गया है और इसे निम्नलिखित अनुसार सारबद्ध किया गया है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की विक्रियां	मी. टन	42,604	53,129	1,31,185	1,22,462	2,44,924
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	308	287	575
दक्षिण अफ्रीका से आयात	मी. टन	15,534	17,638	18,314	9,679	19,359
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	118	62	125
पाटनरोधी शुल्क आकर्षित करने वाले आयात	मी. टन	83,101	87,637	38,085	11,200	22,400
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	46	13	27
अन्य देशों से आयात	मी. टन	1,83,239	1,82,812	1,72,570	55,901	1,11,801
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	94	31	61
कुल मांग	मी. टन	3,24,477	3,41,215	3,60,154	1,99,242	3,98,484
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	111	61	123

69. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में जांच की अवधि और क्षति की अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है।

पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव

i. आयात की मात्रा और आयातों का बाजार अंश

70. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि पाटित आयातों में भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष अथवा निरपेक्ष संदर्भ में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तथापि, वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क लागू रहा है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त किए गए सौदा-वार आयात संबंधी डाटा पर भरोसा किया है। क्षति जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा और पाटित आयातों के अंश का विश्लेषण किया गया है, जो इस प्रकार है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
दक्षिण अफ्रीका	मी. टन	15,534	17,638	18,314	9,679	19,359
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	118	62	125
पाटनरोधी शुल्क आकर्षित करने वाले देश	मी. टन	83,101	87,637	38,085	11,200	22,400
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	46	13	27
ईयू	मी. टन	4,213	15,825	4,410	3,076	6,152
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	376	105	73	146
कोरिया	मी. टन	54,768	53,557	25,802	2,840	5,680
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	47	5	10
सिंगापुर	मी. टन	24,120	18,254	7,873	5,284	10,568
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	33	22	44
अन्य	मी. टन	1,83,239	1,82,812	1,72,570	55,901	1,11,801
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	94	31	61
सकल जोड़	मी. टन	2,81,874	2,88,087	2,28,970	76,780	1,53,560
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात						
कुल आयात	%	6%	6%	8%	13%	13%

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	145	229	229
भारतीय उत्पादन	मी. टन	36%	33%	13%	8%	8%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	37	21	21
भारतीय मांग	%	5%	5%	5%	5%	5%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	106	101	101

71. यह देखा गया है कि :-

- संबद्ध देश से आयातों में जांच की अवधि सहित पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- कुल आयातों में विगत वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देश से आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है।
- भारतीय उत्पादन के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातों में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है जबकि भारत में नई क्षमताएं स्थापित हुई हैं। मांग के संदर्भ में संबद्ध देश से आयात क्षति अवधि के दौरान उतने ही रहे हैं।

पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

72. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार, प्राधिकारी को कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत के दमन, यदि कोई हो, के संदर्भ में घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करना अपेक्षित है। संबद्ध देश से पाटित आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत के दमन, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन से, संबद्ध देश से आयातों की पहुंच लागत के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत, निवल बिक्री वसूली, और एन आई पी की तुलना की गई है।

i. कीमत कटौती

73. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों से कीमतों में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की सभी निवल छूटों और करों के साथ उत्पाद की पहुंच कीमत और औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की है। आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू कीमतों और कटौती के मार्जिन को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
निवल बिक्री प्राप्ति	रु/ मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	122	94	94
पहुंच कीमत	रु/ मी.टन	55,588	63,645	88,795	75,131	75,131
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	160	135	135
कीमत कटौती	रु/ मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	40-60	40-60	0-20	0-20	0-20

74. यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है, जो कि सकारात्मक कीमत कटौती को दर्शा रही है।

ii. कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण

75. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण मात्रा में दबाने के लिए है अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा हो गई होती, अतः प्राधिकारी ने, जब पाटनरोधी शुल्क लागू किया था, तो क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की लागतों व कीमतों में परिवर्तन की जांच की है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिककृत
बिक्रियों की लागत	रु/ मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	117	101	101
बिक्री कीमत	रु/ मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	122	94	94
पहुँच कीमत	रु/ मी.टन	55,588	63,645	88,795	75,131	75,131
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	160	135	135

76. यह देखा जाता है कि जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और आयातों की पहुँच कीमत में 2018-19 तक वृद्धि हुई, उसके बाद उसमें गिरावट आई। बिक्री लागत में 2018-19 तक वृद्धि हुई और उसके बाद गिरावट आई। यह भी नोट किया जाता है कि आयातों की पहुँच कीमत 2018-19 को छोड़कर पूरी क्षति अवधि में बिक्री लागत से कम थी।

77. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण किया है। घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण कीमत हास भी हुआ है।

iii. कम कीमत पर बिक्री

78. संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत से एनआईपी की तुलना कर कम कीमत पर बिक्री का मूल्यांकन किया गया है।

विवरण	इकाई	दक्षिण अफ्रीका
पहुँच कीमत	रु./मी. टन	75,131
क्षति रहित कीमत (बल्क)	रु./मी. टन	***
कम कीमत पर बिक्री	रु./मी. टन	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	0-10

79. एनआईपी से पहुँच कीमत की तुलना पर यह नोट किया जाता है कि कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है।

घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

80. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:-

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

81. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक*	वार्षिकीकृत
प्रति वर्ष क्षमता	मी. टन	76,750	76,750	1,600,83	1,38,375	2,76,750
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	209	361	361
उत्पादन	मी. टन	43,524	53,490	1,38,431	1,26,634	2,53,268
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	123	318	582	582
क्षमता उपयोग	%	57	70	86	92	92
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	123	152	161	161
घरेलू बिक्री	मी. टन	42,604	53,129	1,31,185	1,22,462	2,44,924
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	125	308	575	575

* चूंकि जांच की अवधि 6 माह है, अतः क्षमता 6 माह की अवधि के लिए उपयुक्त रूप से समायोजित की गई है और आधार वर्ष के आंकड़ों को समायोजित करते हुए तदनुसार विश्लेषण किया गया है।

82. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- घरेलू उद्योग ने क्षमता 2018-19 में मैसर्स दीपक फेनोलिक्स लि. द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किए जाने के साथ क्षति की अवधि के दौरान बढ़ी है।
- क्षति की अवधि में उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में क्षति की अवधि में सुधार हुआ।

ii. मांग में बाजार हिस्सा

83. आरोपित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग	%	13	16	36	61	61
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	119	277	468	468
संबद्ध देश	%	4.8	5.2	5.1	4.9	4.9
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	108	106	101	101
वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है	%	26	26	11	6	6
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	41	22	22
अन्य देश	%	56	54	48	28	28
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	95	85	50	50

84. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षमता में वृद्धि के साथ क्षति की अवधि में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, मांग में संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा क्षति की अवधि में लगभग समान रहा है।

iii. मालसूची

85. संबद्ध सामानों की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	110	301	591	591

86. यह देखा जाता है कि उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के कारण 2018-19 में और जांच की अवधि में मालसूची के स्तर में काफी वृद्धि है।

iv. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ एवं निवेश पर आय

87. लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखितानुसार है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
बिक्री की लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	115	117	101	101
बिक्री कीमत	₹/मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	111	122	94	94
प्रति इकाई लाभ	₹/मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	71	163	15	15
कुल लाभ/(हानि)	लाख ₹.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	90	647	118	118
नकद लाभ	लाख ₹.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	88	668	315	315
पीबीआईटी	लाख ₹.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	97	376	242	242
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	80	52	18	18

88. यह देखा जाता है कि प्रति यूनिट लाभ में आधार वर्ष से 2017-18 तक गिरावट आई और उसके बाद 2018-19 में वृद्धि हुई तथा फिर जांच की अवधि में काफी गिरावट आई। निवेश पर आय में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई।

v. रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता

89. रोजगार एवं मजदूरी के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	97	197	197	197
वेतन एवं मजदूरी	लाख ₹.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	115	171	120	240
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	123	318	582	582

90. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है।

vi. वृद्धि

91. वृद्धि के संबंध में संक्षिप्त स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन	वर्ष/वर्ष	23	159	83
घरेलू बिक्री	वर्ष/वर्ष	25	147	87
क्षमता उपयोग	वर्ष/वर्ष	23	24	(8)
औसत मालसूची	वर्ष/वर्ष	10	174	96
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	वर्ष/वर्ष	19	134	69
लाभ/हानि	वर्ष/वर्ष	(10)	615	(82)
नकद लाभ	वर्ष/वर्ष	(12)	659	(53)
पीबीआईटी	वर्ष/वर्ष	(3)	289	(36)
नियोजित पूंजी पर आय	वर्ष/वर्ष	(20)	(35)	(66)

92. यह नोट किया जाता है कि इस अवधि में घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मानदंडों ने वृद्धि दर्शाई है। जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, मात्रात्मक मानदंड ने घरेलू उद्योग द्वारा क्षमताओं में वृद्धि के कारण सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है।

vii. पाटन मार्जिन

93. यह पाया जाता है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है। संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन हो रहा है।

viii. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

94. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का पहुँच मूल्य केवल उसकी निवल बिक्री कीमत से कम ही नहीं है बल्कि घरेलू उद्योग की एनआईपी से भी कम है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों की पहुँच कीमतों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण किया है जिससे जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। तीसरे देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर या तो पाटनरोधी शुल्क लग रहा है अथवा वे न्यूनतम स्तर पर हैं या उच्चतर कीमतों पर हैं। पाटित आयात बाजार में उत्पाद की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

ix. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

95. विचाराधीन उत्पाद में हाल ही में काफी निवेश किया गया था। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में काफी गिरावट की हानि हो रही है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के सामने आ रही प्रतिस्पर्धा से उद्योग के प्रचालन प्रभावित हुए हैं जिससे उसकी पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है। घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है और इसीलिए पूंजी निवेश जुटाने में क्षमता अकेले उत्पाद के निष्पादन के आधार पर नियंत्रित नहीं होती है।

x. क्षति मार्जिन की मात्रा

96. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए एनआईपी पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम

उपयोग पर विचार किया गया है। जांच की अवधि में उत्पादन का परिकलन सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करके किया गया है और उसी उत्पादन पर प्रति यूनिट निर्धारित लागत निकालने के लिए विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय उत्पादन लागत में न लगाए जाएं। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार और अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी। घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत निर्धारित की गई है और कम कीमत पर बिक्री निकालने के लिए संबद्ध सामानों के पहुँच मूल्य के साथ उसकी तुलना की गई है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम था, जैसा कि सकारात्मक क्षति मार्जिन दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है।

विवरण	इकाई	दक्षिण अफ्रीका
पहुँच कीमत	रु./मी. टन	75,131
क्षति रहित कीमत	रु./मी. टन	***
क्षति मार्जिन	रु./मी. टन	***
	%	***
	रेंज	0-10

क्षति का समग्र मूल्यांकन

97. संबद्ध सामानों के आयातों की जांच और घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित दर्शाता है:

- I. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में पूर्ण दृष्टि से और कुल आयातों की तुलना में वृद्धि हुई है।
- II. संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और कम कीमत पर बिक्री भी सकारात्मक है।
- III. संबद्ध देश से आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया है। घरेलू उद्योग में संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण कीमत न्यूनीकरण भी हुआ है।
- IV. क्षति की अवधि में उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।
- V. घरेलू उद्योग के निष्पादन का लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में काफी ह्रास हुआ है।

घ. कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोप्य विश्लेषण

98. धारा 9 क (5) के तहत, प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस बात पर ध्यान न देते हुए पाटन और क्षति की संभावना तथा दायित्वों को जारी रखने की आवश्यकता की जांच करें कि क्या समीक्षा जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के कोई आयात हुए हैं अथवा नहीं। इस बात की नीचे जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान रहा है।

i. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

99. यह देखा जाता है कि तीसरे देशों से आयातों पर या तो पाटनरोधी शुल्क लग रहा है या पाटनरोधी शुल्क जांच के तहत हैं या उच्चतर कीमतों पर हैं। अतः तीसरे देशों से आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ii. मांग में संकुचन

100. यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति की अवधि में बढ़ी है। अतः मांग में संकुचन को घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

iii. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

101. घरेलू उद्योग ने नगण्य मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। अतः घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित ह्रास घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं हैं।

iv. प्रौद्योगिकी में विकास

102. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया में कोई खास विकास नहीं हुआ है। प्रौद्योगिकी में संभावित विकास घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

v. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

103. आवेदकों द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है। आवेदक मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना वर्तमान प्रयोजन के लिए संगत सूचना है और आवेदकों ने घरेलू उद्योग के रूप में यह सूचना दी है।

vi. प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

104. जांच में यह बात सामने नहीं आई है कि प्रतिस्पर्धा की शर्तें या व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी हैं।

vii. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

105. विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत के पैटर्न में परिवर्तनों से घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति नहीं हुई है। वस्तुतः संबद्ध सामानों के लिए मांग संगत अवधि में बढ़ी है।

ट. क्षति जारी रहने और कारणात्मक संपर्क का विश्लेषण**ठ. पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना**

106. प्राधिकारी यह पाते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस जांच का जोर, पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की अनुमति दिए जाने की स्थिति में और यहां तक कि यदि वर्तमान में कोई क्षति नहीं है तो निरंतर पाटन और परिणामस्वरूप क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करने पर है।

ठ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

107. घरेलू उद्योग ने पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- I. विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सभी पूर्व जांचों में निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक रहा है।
- II. पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी में काफी आयात पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में बढ़े हुए आयात की संभावना दर्शाते हैं।
- III. संबद्ध देश में उत्पादक द्वारा धारित अतिरिक्त उत्पादन क्षमताएं काफी हैं। उत्पादक के पास 40,000 मी. टन की क्षमता है जिसकी घरेलू बाजार में कोई मेल खाती हुई मांग नहीं है।
- IV. विदेशी उत्पादक के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताएं शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में बढ़े हुए आयातों की संभावना दर्शाती हैं। कम घरेलू मांग के कारण उत्पादक के पास लगभग 36,800 मी. टन की अनुमानित मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता है।
- V. संबद्ध देश में निर्यातक के पास काफी अनुपयुक्त क्षमताएं हैं।
- VI. संबद्ध देश में उत्पादक की निर्यातोन्मुखता बहुत अधिक उनकी क्षमता के लगभग 75 प्रतिशत है।
- VII. उत्पादक पूर्व प्रभावी रूप से निर्यातोन्मुख है और भारतीय बाजार उनके हितों के लिए महत्वपूर्ण है। कुल निर्यातों के लगभग 65-70 प्रतिशत निर्यात भारतीय बाजार को किया जाता है।
- VIII. उत्पादक पाटन के आदी हैं, जैसा कि विभिन्न बाजारों को निर्यातों के संबंध में कीमत अंतर से देखा जा सकता है।
- IX. एशियाई देशों में अधिक क्षमता, चीनी उद्योग की स्व-पर्याप्तता से बाजार में फिनोल की अधिक आपूर्ति हुई है। इससे बाजार परिदृश्य काफी बदला है।

- X. फिनोल में व्यापार का बदलता पैटर्न है जिससे भारत में आयातों का स्रोत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने तथा बंद किए जाने के अनुरूप बदलता है।
- XI. वैश्विक रूप से बाजारों में फिनोल अतिरिक्त मात्राओं में मौजूद है, क्योंकि इस उत्पाद की अधिक आपूर्ति हुई है।
- XII. भारत संबद्ध देश के निर्यातकों के लिए लाभकारी बाजार है और भारतीय बाजार की तरह कोई दूसरा बाजार इस तरह की संभावनाएं नहीं देता। जिन कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का निर्यात निर्यातक दूसरे बाजारों में कर रहा है, वे भारत से कम हैं।
- XIII. भारत में बढ़ी हुई घरेलू क्षमताएं होने से गैर-अनिवार्य आयातों में वृद्धि है।
- XIV. दक्षिण अफ्रीका से भारत को निर्यात कीमत शेष विश्व को निर्यात कीमत से निरंतर कम थी। भारत को कम निर्यात कीमत और पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद भारत दक्षिण अफ्रीका के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रमुख निर्यात लक्ष्य रहा है।
- XV. घरेलू उद्योग का बाजार में बिक्री करना अधिकार है और पाटित आयातों से उसे दूर नहीं किया जा सकता।
- XVI. प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन पर संभावना के आधार के रूप में विचार किया है। इस मामले में, क्षति मार्जिन जांच की अवधि में सकारात्मक है जो स्पष्ट रूप से पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में संभावना सिद्ध करता है।
- XVII. इस समय विश्व के सामने भारत को एक अपवाद मानकर अधिक क्षमता की समस्या है। अतः भारत फिनोल के सभी निर्यातकों के लिए सबसे अधिक वांछनीय बाजार बन गया है।
- XVIII. एशिया में धीमी मांग से अन्य निर्यातक देश भारत को आक्रामक रूप से निर्यात करेंगे। भारत दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रमुख निर्यात लक्ष्य है, अतः उसके पास भारतीय बाजार में बने रहने के लिए अपनी कीमतें कम करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं होगा।

ठ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

108. पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - I. दक्षिण अफ्रीका अग्रिम लाइसेंस के तहत भारत में केवल छोटी सी मांग की पूर्ति करता है और निर्यात आकर्षक नहीं हैं क्योंकि दूसरे देशों की उच्चतर कीमतें हैं।
 - II. अनिवार्य तथा गैर-अनिवार्य आयातों संबंधी अनुरोध असंगत हैं। घरेलू उद्योग उस तरह का कार्य करता है, मानो प्रतिस्पर्धा पर ध्यान न देते हुए अपनी पूर्ण क्षमता से बाजार में बिक्री करने का उनका अधिकार है।
 - III. घरेलू उद्योग पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में अपने मामले के समर्थन में कोई साक्ष्य देने में विफल रहा है।
 - IV. दक्षिण अफ्रीका में कोई अतिरिक्त अथवा अनुपयुक्त क्षमता नहीं है और शुल्क मुक्त योजनाओं के तहत आयात किए ही जाने हैं क्योंकि घरेलू उद्योग पूरी मांग को पूरा नहीं कर सकता। अन्य स्रोतों से भी आयात जारी रहेंगे।
 - V. पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर आयातों में कोई उछाल नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से आयात स्थिर हैं और लगातार स्थिर रहे हैं।
 - VI. पाटन और क्षति दोनों की मौजूदगी अथवा बार-बार होने अपेक्षित हैं ताकि पाटनरोधी शुल्क जारी रखा जा सके।
 - VII. संभावना के लिए, ऐतिहासिक पाटन मार्जिन इस कारण काफी रहा है कि पाटन मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया था।

- VIII. भारत एक कीमत संवेदी बाजार तथा दक्षिण अफ्रीकी निर्यातों के लिए सबसे बड़ा बाजार है और इसीलिए आर्थिक मानदंड कम कीमत की अनुमति देते हैं, अतः कीमतें दूसरे देशों को निर्यातों से कम हैं।
- IX. दक्षिण अफ्रीका की क्षमता 40,000 मी. टन की है, जो विचाराधीन उत्पाद के लिए भारत की मांग के केवल 10 प्रतिशत के बराबर है। अनुपयुक्त क्षमताएं केवल 6,000 मी. टन हैं जो भारत में मांग की तुलना में नगण्य मात्रा है जो 3,80,000 मी. टन बनती है। मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता के दावे भ्रामक हैं।
- X. चीन और थाइलैंड दक्षिण अफ्रीका के निर्यात बाजार नहीं हैं और इसीलिए इन देशों में विस्तार असंगत है।
- XI. व्यापार परिवर्तन पैटर्न असंगत है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से आयात पिछले 18 वर्षों से उन पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद जारी रहे हैं।
- XII. दक्षिण अफ्रीका चीन को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं करता और दूसरे क्योंकि जिन देशों पर चीन ने पाटनरोधी शुल्क लगाया है, उनमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं है। अतः चीनी उद्योग की कोई संगतता नहीं है।
- XIII. दक्षिण अफ्रीका एशिया में किसी तथाकथित धीमी मांग से प्रभावित नहीं होने जा रहा है क्योंकि वह उसका प्रमुख बाजार नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह साक्ष्य 2013 से संबंधित है।
- XIV. चूंकि प्रति यूनिट वसूली भारत में सबसे कम है, अतः वह दक्षिण अफ्रीका के लिए लाभकारी बाजार नहीं हो सकता।
- XV. गैर-अनिवार्य आयात का विचार कानून में संधारणीय नहीं है। दक्षिण अफ्रीका से भारत में अनिवार्य आयातों के लिए मांग पूरी करने हेतु अपने सभी उत्पादन भारत की ओर भेजने और अन्य आकर्षक बाजारों को खोने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
- XVI. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि विदेशी उत्पादकों के क्षमता उपयोग का स्तर काफी कम है, घरेलू उद्योग के अपने ही आंकड़ों का विरोधाभासी है जो यह दर्शाता है कि दक्षिण अफ्रीका में क्षमता उपयोग अत्यधिक 80 प्रतिशत पर है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

109. प्राधिकारी की जानकारी में लाए गए सभी कारकों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की गई है कि क्या शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटन या क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। प्राधिकारी ने पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है।
110. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से उपलब्ध वास्तविक आयातों के आंकड़ों का प्रयोग किया है और अनिवार्य तथा गैर-अनिवार्य आयातों के बीच कोई भेद नहीं किया है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है।
111. प्राधिकारी ने धारा 9 क (5) में उल्लिखित अपेक्षा, नियम 23 और नियमावली के अनुबंध-II(vii) के संदर्भ में वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच की है। वर्तमान जांच चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह निर्धारित करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाया जाना आवश्यक है। इसमें इस बात पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है कि क्या लगाये गये शुल्क से क्षतिकारक पाटन समाप्त करने का प्रत्याशित प्रयोजन पूरा हो रहा है। ऐसा संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशेष सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का प्रावधान है जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, यथा:-
 - I. पर्याप्त रूप से बड़े हुए आयात की संभावना दर्शाते हुए भारत को पाटित आयातों की काफी वृद्धि दर।
 - II. कोई अतिरिक्त निर्यात खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजारों को काफी बड़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना दर्शाने वाली निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, अथवा आसन्न, काफी वृद्धि।

- III. क्या आयात उन कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव होगा और जिनसे और आयात के लिए मांग में वृद्धि की संभावना होगी; और
- IV. जांच की जा रही वस्तु की मालसूची।

I. सतत् एवं विद्यमान पाटन और क्षति

112. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात जांच की अवधि और आगे जांच की अवधि के बाद की अवधि सहित क्षति अवधि में बढ़ते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पाटन मार्जिन सकारात्मक है। यह भी देखा जाता है कि ये आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर हैं। पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने की संभावना है।

II. संबद्ध देश में अधिशेष क्षमताएं

113. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सूचना का सार निम्नलिखित रूप में किया है:

विवरण	दक्षिण अफ्रीका
क्षमता	40,000
उत्पादन	34,000
घरेलू मांग	4,000
अधिशेष क्षमताएं	36,000

114. यह देखा जाता है कि निर्यातकों के पास क्षमता का बड़ा भाग अधिशेष है। घरेलू मांग कंपनी द्वारा सृजित क्षमता का केवल 10 प्रतिशत पूरा कर सकती है।
115. यह देखा जाता है कि निर्यातक के पास उसकी क्षमताओं के 15 प्रतिशत तक अनुपयुक्त क्षमताएं हैं।

विवरण	मात्रा (मी. टन)
क्षमता	40,000
उत्पादन	34,000
उपयोग की गई क्षमताएं	6,000

116. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक के पास काफी मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताएं हैं जो पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में भारत की ओर भेजी जा सकती हैं।

विवरण	इकाई	2015	2016	2017	2018
क्षमता	मी. टन	40,000	40,000	40,000	40,000
उत्पादन	मी. टन	34,000	34,000	35,000	34,000
उपयोग की गई क्षमताएं	मी. टन	6,000	6,000	5,000	6,000
निर्यात	मी. टन	23,227	32,253	34,898	30,818
मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता	मी. टन	29,227	38,253	39,898	36,818

III. कीमत कटौती और बाजार के रूप में भारत की आकर्षकता

117. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक है और इस प्रकार वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने से गहन पाटन होने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को बिक्री की कम मात्रा, कम बिक्री कीमत और लाभ में गिरावट के रूप में क्षति होगी।

118. प्राधिकारी के लिए यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि घरेलू बाजार अर्थात् भारत में विद्यमान कीमत तीसरे देशों को निर्यातित मात्रा की दिशा बदलने के लिए निर्यातक के लिए आकर्षक है। यह नोट किया जाता है कि आयातों का पहुँच मूल्य जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से कम है।
119. यह देखा जाता है कि निर्यातक का 91 प्रतिशत उत्पादन और 77 प्रतिशत क्षमता देश में कम घरेलू मांग के कारण जांच की अवधि में निर्यात के लिए लक्षित थी। निर्यातक अधिकतर निर्यात के लिए सामानों का उत्पादन कर रहा है।

विवरण	मात्रा (मी. टन)
क्षमता	40,000
उत्पादन	34,000
निर्यात	30,818
निर्यातोन्मुख	
उत्पादन के प्रतिशत के रूप में	91%
क्षमता के प्रतिशत के रूप में	77%

120. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों का विवरण, जैसा कि ट्रेड मैप पर उपलब्ध है, निम्नलिखित है:

निर्यात का उद्देश्य	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
भारत	18,475	19,376	18,368	11,830	23,660
बेल्जियम	-	1,585	350	3,034	6,068
ब्राजील	3,269	4,394	2,634	1,004	2,009
तैपई, चीनी	1,788	2,075	1,722	842	1,684
अर्जेंटीना	338	753	696	529	1,059
न्यूजीलैंड	1,093	1,218	1,280	463	927
मिस्र	-	80	583	256	512
कोरिया	100	1,220	560	120	241
यूनाइटेड किंगडम	4,644	2,157	3,573	110	220
अन्य	2,546	2,039	1,053	301	603
कुल	32,253	34,898	30,818	18,491	36,982

121. यह देखा जाता है कि भारत ऐतिहासिक रूप से लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध देश के लिए प्रमुख निर्यात लक्ष्य है। भारत को निर्यात दक्षिण अफ्रीका से फिनोल के कुल निर्यातों का 64 प्रतिशत हैं। इसके अतिरिक्त, दक्षिण अफ्रीका में 59 प्रतिशत कुल फिनोल क्षमता और 70 प्रतिशत कुल उत्पादन भारत को निर्यात किया जा रहा है। ट्रेड मैप से यह भी पाया जाता है कि जब निर्यात कीमतों से तुलना की जाए जिन पर दक्षिण अफ्रीका ने 2019 में तीसरे देशों को निर्यात किया तो दक्षिण अफ्रीका से भारत को संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत निरंतर सबसे कम रही है।

पाटन एवं क्षति की संभावना संबंधी निष्कर्ष

122. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा जांच की अवधि सहित पूरी क्षति अवधि में पूर्ण दृष्टि से बढ़ी है। संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है। संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण और ह्रास कर रहे हैं। घरेलू उद्योग के निष्पादन का जांच की अवधि के दौरान काफी ह्रास हुआ है। घरेलू उद्योग को वर्तमान अवधि के दौरान निरंतर क्षति हुई है। यह देखा जाता है कि पाटन की स्पष्ट संभावना और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति है। संबद्ध देश से पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन वर्तमान निर्णायक समीक्षा सहित उत्तरवर्ती समीक्षाओं के

दौरान सकारात्मक बनी हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से किसी भी उत्पादक तथा निर्यातक ने वर्तमान जांचों के दौरान सहयोग नहीं किया है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि निर्यातक के पास अधिशेष उत्पादन क्षमताएं, अनुपयुक्त क्षमताएं और मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताएं हैं जिनके पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में भारत को भेजे जाने की संभावना है। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह भी दर्शाता है कि संबद्ध देश का निर्यातक अत्यधिक निर्यातोन्मुख है और निर्यात के लिए व्यापक रूप से सामानों का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जब तीसरे देशों को निर्यात कीमतों से तुलना की जाए तो दक्षिण अफ्रीका से भारत को सामानों का निर्यात कीमत निरंतर सबसे कम रही है। भारत संबद्ध देश के लिए एक प्रमुख निर्यात लक्ष्य रहा है। इस प्रकार, ये सभी मानदंड यह दर्शाते हैं कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों में निर्यातकों के पाटित कीमतों पर भारत में पाटित उत्पादों का निर्यात गहन करने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को बार-बार क्षति होगी।

ड. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

123. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हो गए हैं। प्राधिकारी ने उन दोहराए गए अनुरोधों सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध की जांच की है जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है तथा इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से हल कर दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए मुद्दों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है।

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

124. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- i. अग्रवाल केमिकल को वर्तमान जांच में आयातक नहीं माना जा सकता क्योंकि कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका से फिनोल का आयात नहीं किया है।
- ii. सासोल साउथ अफ्रीका (पीटीवाई) लिमिटेड को वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता क्योंकि उसने खुद को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं किया है और न ही प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।
- iii. फेडरेशन ऑफ इंडियन प्लाइवुड एंड पैनल इंडस्ट्री को एक असहयोगी माना जाना है क्योंकि वे समय-सीमा के भीतर अपने प्रयोक्ताओं से संबंधित सूचना अथवा कोई टिप्पणियां दायर करने में विफल रहे हैं और उनके किसी सदस्य ने भी प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं।
- iv. सेंचुरी प्लाई को असहयोगी माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं।
- v. संबद्ध देश से पाटन मार्जिन सकारात्मक है। संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन हो रहा है।
- vi. आयातों की मात्रा आधार वर्ष से तुलना करने पर पूर्ण दृष्टि से बढ़ी है।
- vii. कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, आयात कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण तथा ह्रास कर रही हैं।
- viii. घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभप्रदता और आरओसीई के संबंध में ह्रास हुआ है।
- ix. घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई है। पाटित आयातों को छोड़कर कोई अन्य ज्ञात कारक घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं।
- x. पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति होने की संभावना है।
- xi. उत्पादक पाटन के आदी हैं, जैसा कि विभिन्न बाजारों में निर्यातों के संबंध में कीमत संबंधी अंतर से देखा जा सकता है।
- xii. एशियाई देशों में अधिक क्षमता, चीनी उद्योग की स्व-पर्याप्तता से बाजार में फिनोल की अधिक आपूर्ति हुई है। इससे बाजार परिदृश्य काफी परिवर्तित हुआ है।

- xiii. फिनोल के व्यापार में परिवर्तित पैटर्न है जिससे भारत में आयातों का स्रोत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और बंद किए जाने के बीच परिवर्तित होता है।
- xiv. भारत में बढ़ी हुई घरेलू क्षमताओं की मौजूदगी में गैर-अनिवार्य आयातों में वृद्धि है।
- xv. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि प्रपत्र बी और डी और एनआईपी पर्याप्त रूप से प्रकट की जानी चाहिए।
- xvi. जांच की अवधि में संबद्ध देश से आयातों की कम मात्रा को देखते हुए, पूरी क्षति अवधि में संबद्ध देश से आयातों में निरंतर वृद्धि और जांच की अवधि के बाद संबद्ध देश से आयातों में काफी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वही शुल्क बढ़ाया जाना अपेक्षित है।
- xvii. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे उसी रूप में और यूएसडी के संदर्भ में पाटनरोधी शुल्क जारी रखें।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

125. प्रकटन विवरण पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध नीचे पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं:

- i. प्रकटन विवरण में मैसर्स हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स केमिकल लि. और मैसर्स दीपक फेनोलिक्स के लिए आयातों की घोषणा का तथ्य केवल संबद्ध देश अर्थात् दक्षिण अफ्रीका के लिए रिकार्ड किया गया है और इन दो उत्पादकों से अन्य देशों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है/प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया प्रा. लि. द्वारा किए गए आयातों के ब्यौरे भी संबद्ध देश अर्थात् दक्षिण अफ्रीका से हैं और अन्य देशों से एसआई ग्रुप इंडिया प्रा. लि. द्वारा किए गए आयातों के कोई ब्यौरे अथवा विश्लेषण नहीं किए गए हैं।
- ii. प्रकटन विवरण में, मैसर्स हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स केमिकल लि. और मैसर्स दीपक फेनोलिक्स लि. द्वारा आयातों की घोषणा की अवधि भी निर्धारित नहीं की गई है।
- iii. आवेदन प्रपत्र के अनुसार आयातों की घोषणा घरेलू उद्योग द्वारा विशेष रूप से जांच की अवधि के लिए और अनिवार्य रूप से संबद्ध देश सहित सभी देशों के लिए पूर्व तीन वर्षों के लिए की जानी अपेक्षित है। घरेलू उत्पादकों द्वारा आयातों का विश्लेषण केवल जांच की अवधि के संबंध में ही नहीं बल्कि पिछले वर्षों के लिए भी किया जाना अपेक्षित है।
- iv. इस जांच में छः माह की जांच की अवधि मानने के समर्थन में एक मात्र कारण, जो प्रकटन विवरण में रिकार्ड किया गया है, वह आयात कीमतों में भारी गिरावट है जिसे किसी तरह भी अपवादात्मक अथवा दुर्लभ स्थिति नहीं माना जा सकता।
- v. बारह माह की जांच की अवधि न माने जाने का तर्क और फिर जांच की अवधि के बाद छः माह सहित छः माह की जांच की अवधि मानने की सूचना स्पष्ट नहीं है। प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन पत्र में छः माह से कम की जांच की अवधि देने का विवेकाधिकार नहीं है क्योंकि व्यापार सूचना 02/2017 में "चाहिए" शब्द कम से कम एक वर्ष की जांच की अवधि अपनाने का अनिवार्य दायित्व दर्शाता है। संदर्भ भारत संघ बनाम कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का दिया गया है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "सकता है" को "जाएगा" नहीं पढ़ा जा सकता। इसके अतिरिक्त, संदर्भ फोरेक इंडिया बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी का दिया गया है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी व्यापार सूचना की अनदेखी नहीं कर सकता और कोई सहानुभूतिपूर्वक और विशेष रियायत किसी पक्षकार को नहीं दी जा सकती।
- vi. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का आधार दर्शा सकते हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के सभी आयात भारी रूप में थे तथा कुछ लेन-देनों को असाधारण वर्गीकृत करने का और उच्च कीमत वाले आयातों को हटाने का आधार भी दर्शा सकते हैं।
- vii. दक्षिण अफ्रीका द्वारा तीसरे देश अर्थात् बेल्जियम निर्यात कीमतों के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण माननीय डीजीटीआर की सतन् परिपाटी से स्पष्ट रूप से अलग होना है।
- viii. घरेलू उद्योग को कोई निरंतर अथवा वर्तमान क्षति नहीं है।

- ix. एसएआरएस के आंकड़ों के आधार पर आईटीसी परिकलनों के आधार पर निकाले गए दक्षिण अफ्रीका से तीसरे देशों को निर्यातों की कीमतों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि न तो बिक्री की मद और न ही उसकी शर्तें सुनिश्चित की जा सकती हैं। इन आंकड़ों में उल्लिखित कीमतें हमेशा कुछ अवधारणाओं पर आधारित होती हैं और वे देश के लिए अनुमानित सामान्य मूल्य निकालने का आधार नहीं बन सकतीं।
- x. प्रकटन विवरण में प्रकट दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध सामानों की आयात मात्राएं घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन पत्र/लिखित अनुरोधों में प्रकट किए गए आयात आंकड़ों की तुलना में काफी अंतर पर हैं।
- xi. मांग के लिए आंकड़े बिक्री लागत के लिए और बिक्री कीमतों तथा पहुँच मूल्य के लिए सूचियां आवेदन पत्र में और प्रकटन विवरण में भिन्न हैं।
- xii. पहुँच मूल्य आधार वर्ष अर्थात् 2016-17 की तुलना में 2018-19 में 60 प्रतिशत तक बढ़ा है, जबकि घरेलू बिक्री कीमतें 22 प्रतिशत तक ही बढ़ पाईं। प्रकटन विवरण में इस परिदृश्य के लिए कोई कारण/विश्लेषण नहीं है कि घरेलू उद्योग पहुँच मूल्य में 60 प्रतिशत वृद्धि के स्तर तक अपनी कीमतें क्यों नहीं बढ़ा पाया।
- xiii. घरेलू उद्योग के लाभ और आरओसीई में दीपक फेनोलिक्स के संयंत्र के दीपक फेनोलिक्स की उच्च उत्पादन लागत के कारण पूर्णतः प्रचालनात्मक होने के परिणामस्वरूप जांच की अवधि में गिरावट आई और अन्यथा नहीं।
- xiv. जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) के लिए नकद लाभ के आंकड़े गलत प्रतीत होते हैं क्योंकि उन्हें वार्षिकीकृत नहीं किया गया है।
- xv. मालसूची का विश्लेषण करने का सही तरीका बिक्री की प्रतिशतता और मालसूची के दिवसों की संख्या के रूप में उनकी जांच करना है और किसी अन्य आधार पर मालसूची का विश्लेषण करने से भ्रामक एवं गलत निष्कर्ष निकलेंगे।
- xvi. प्रकटन विवरण में पैरा 112 से 121 में पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के संबंध में यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग के अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत किया गया है और उनका वस्तुपरक रूप से विश्लेषण किए बिना उन्हें स्वीकार किया गया है।
- xvii. वह अवधि अत्यधिक रूप से लंबी रही है जिसके लिए दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध सामानों के आयातों पर 2003 से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।
- xviii. आवेदकों ने निम्नलिखित उदाहरणों में नियमावली के तहत गोपनीयता के लिए प्रावधानों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की है:
 - क. मी. टन में घरेलू उद्योग की वास्तविक क्षमता।
 - ख. मी. टन में घरेलू उद्योग का वास्तविक उत्पादन।
 - ग. मी. टन में घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा; और
 - घ. प्रतिशत में बाजार हिस्सा तथा मांग।
- xix. घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मानदंडों पर स्पष्ट रूप से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। आवेदन पत्र में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर कोई कीमत प्रभाव न होना दर्शाते हैं।
- xx. दक्षिण अफ्रीका में क्षमताओं में कोई विस्तार नहीं हुआ है और दक्षिण अफ्रीका से आयातों की मात्रा निरंतर कम रही है जिसमें समग्र गिरावट की प्रवृत्ति रही है।
- xxi. दक्षिण अफ्रीका में केवल लगभग 6000 मी. टन की अनुपयुक्त क्षमता है और वह भारत में कुल मांग की केवल 1 प्रतिशत – 2 प्रतिशत है जो किसी भी तरह अत्यधिक नहीं है और यहां तक कि यदि तर्क के लिए यह माना जाए कि उपर्युक्त अनुपयुक्त क्षमता शुल्कों की वापसी के बाद भारत को निर्यात की जाएगी तो इसका भारतीय बाजार पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

- xxii. वर्तमान वास्तविक मैट्रिक्स में तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि तथाकथित क्षति तथा क्षति की संभावना और दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध सामानों के सतत् आयातों के बीच कोई कारणात्मक संपर्क है।
- xxiii. थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से फिनोल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में जांच की अवधि और वर्तमान जांच में क्षति की अवधि अतिव्यापन करते हैं। जांच की अवधि के थाइलैंड के प्राथमिक जांच परिणामों में प्राधिकारी की जांच स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एचओसीएल का निष्पादन कई अन्य कारकों से प्रभावित होना सिद्ध हुआ है और घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन के कारण न हुई मानी गई है। अतः जापान और थाइलैंड से फिनोल के मामले में कारणात्मक संपर्क में कटाव से संबंधित जांच परिणाम वर्तमान जांच पर लागू हैं। यह एक सिद्ध तथ्य है कि एचओसीएल को क्षति उनके स्वयं से प्रभावित है जो उन कारकों के आधार पर है जो दक्षिण अफ्रीका से आयातों के कारण नहीं हैं। अतः घरेलू उद्योग को क्षति का दावा दक्षिण अफ्रीका से आयातों के कारण होने के लिए रद्द किए जाने योग्य है।
- xxiv. आवेदन पत्र में दिए गए मानदंड पूर्ण रूप से यह स्पष्ट करते हैं कि आवेदकों को आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई और क्षति यदि कोई हुई है तो वह स्पष्ट रूप से दक्षिण अफ्रीका से आयातों के कारण नहीं है।
- xxv. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत भाड़ा, कमीशन और पत्तन खर्चों के लिए 5 प्रतिशत के समायोजनों का आधार सिद्ध नहीं किया गया है और विश्वसनीय नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीआईएफ मूल्य से कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए किए गए समायोजनों की मात्रा प्रकट नहीं की है और वे प्रकट करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि यह गोपनीय सूचना नहीं है। आवेदक द्वारा परिकलित निर्यात कीमत बढ़ा-चढ़ाकर दी गई है और प्राधिकारी को उसे पुनः निर्धारित करना है।
- xxvi. ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने पूरी तरह से आवेदक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है और इसीलिए अपनाए गए समायोजन प्रकट किए जाने चाहिए और आवेदक द्वारा भी कोई गोपनीयता का दावा नहीं किया जा सकता।
- xxvii. असहयोगी उत्पादकों, निर्यातकों और देश के लिए सामान्य मूल्य गोपनीय नहीं हो सकता क्योंकि वह व्यापार संवेदी अथवा स्वामित्व वाली सूचना नहीं है। संदर्भ भारत संघ बनाम मेघमणि ऑर्गेनिक्स लि. का दिया गया है जिसमें यह पाया गया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी तब तक किसी सूचना को गोपनीय नहीं मान सकते जब तक उसका दावा न किया गया है।
- xxviii. संबद्ध देश में क्षमता भी भारत में फिनोल के लिए मांग-आपूर्ति अंतराल का 40 प्रतिशत भी पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नगण्य अनुपयुक्त क्षमताओं से तब भी क्षति बार-बार नहीं हो सकती, जब वह भारत को निर्यातों के लिए अनुपयुक्त हो।
- xxix. प्राधिकारी ने इस बात की जांच नहीं की है कि क्या अन्य निर्यात बाजार मौजूद हैं जो अधिशेष क्षमताएं रखने वाले उत्पादक/निर्यातकों द्वारा अतिरिक्त उत्पादन को ले सकें।
- xxx. 22 प्रतिशत आरओसीई लागू नहीं किया जाना है। यह निर्धारण नहीं अपनाया जाना चाहिए क्योंकि यह उस समय किया गया था जब पीएलआर 18 प्रतिशत था। पाटनरोधी करार में वास्तविक लागत अधिदेशित है न कि अनुमानित लागत।
- xxxi. लंबी अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से अंतिम उपभोक्ता के लिए लागत बढ़ती है। प्रयोक्ता उद्योगों को शुल्क जारी रखने की स्थिति में अपूर्ण क्षति होगी।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

126. हितबद्ध पक्षकारों के स्तर के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में प्राधिकारी ने विधिवत रूप से उनकी जांच की है और इस अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराओं में अपने जांच परिणाम रिकार्ड किए हैं।
127. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के संबंध में पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में प्राधिकारी ने संगत मानदंडों की विधिवत जांच की है और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराओं में अपने जांच परिणाम रिकार्ड किए हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए घरेलू उद्योग के आधार,

विचाराधीन उत्पाद, गोपनीयता, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और जांच की अवधि से संबंधित मुद्दों पर उपर्युक्त संगत पैराओं में पहले ही विचार किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में जांच की अवधि स्थापित परिपाटी के अनुसार मानी गई है जो पाटनरोधी नियमावली के अनुरूप है।

128. जहां तक सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए बेल्जियम की उपयुक्तता के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि चूंकि संबद्ध देश से किसी भी निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है और चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने सामान्य मूल्य के लिए कोई विरोधी साक्ष्य नहीं दिया है, अतः प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों पर अर्थात् संबद्ध देश से बेल्जियम को निर्यात कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विश्वास किया है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण अफ्रीका के लिए बेल्जियम दूसरा सबसे बड़ा निर्यात लक्ष्य है, पहला भारत है और उसके भारत को 5 प्रतिशत से अधिक निर्यात हैं।
129. जहां तक आवेदन पत्र और प्रकटन विवरण में आंकड़ों में परिवर्तन का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि आवेदन पत्र में घरेलू उद्योग ने केवल 29071110 के आयात आंकड़ों पर विचार किया था। बाद में यह पाया गया था कि संबद्ध सामानों का आयात एचएस कोड 29071190 के तहत भी किया गया था। प्रकटन विवरण में आयातों में सीमा प्रशुल्क शीर्ष संख्या 29071110 और 29071190 के तहत संबद्ध सामानों के आयात शामिल हैं और तदनुसार आयात तथा अन्य संगत मानदंड संशोधित किए गए हैं।
130. जहां तक उस अवधि का संबंध है, जिसके लिए पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क की अवधि धारा 9क(5) के तहत असंगत है। प्राधिकारी के लिए पाटन के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना तथा परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की जांच करना अपेक्षित है।

ढ. भारतीय उद्योग के हित

131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी तरह संबद्ध देश/क्षेत्र से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
132. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध सामानों का प्रयोग कर विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप, इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों से कम नहीं होगी, विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना घरेलू उद्योग को क्षति दूर करने के लिए किसी आवश्यक धनराशि तक प्रतिबंधित किया जाए। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की परिपाटियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, साथ ही घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट भी रुकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ण. निष्कर्ष

133. उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों, जैसा कि उपर्युक्त जांच परिणाम में रिकार्ड किया गया है, को ध्यान में रखते हुए और घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

क. संबद्ध देश संबद्ध सामानों का सतत पाटन है और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में आयात आने की संभावना है।

ख. घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है और संबद्ध सामानों के पाटन के कारण वह सुभेद्य रहता है।

ग. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना इस स्तर पर लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की अनुमति दिए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना दर्शाती है।

त. सिफारिश

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत, उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति, कारणात्मक संपर्क और पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच शुरू करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना पाटन और क्षति को ऑफसेट करने के लिए अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक समझते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।
135. इन परिस्थितियों में, वर्तमान जांच अवधि के लिए गणना किए गए पाटन और क्षति के मार्जिन के अनुसार, विषय वस्तु से उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तु पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता की सिफारिश करना उचित है। इसके लागू होने की तारीख से 5 साल। प्राधिकरण द्वारा पीछा किए जाने वाले कम शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकरण पाटन के हाशिए के कम समान के बराबर निश्चित पाटनरोधी कर्तव्यों को जारी रखने की सिफारिश करता है और क्षति के मार्जिन को स्थापित किया जाता है, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति को दूर किया जा सके, नीचे दी गई तालिका में वर्णित फ़ॉर्म और तरीके। इस प्रकार, प्राधिकरण पांच साल की आगे की अवधि के लिए नीचे दी गई तालिका 7 में कॉलम 7 के अनुसार विषय देश से विषय वस्तुओं के सभी आयातों पर संशोधित पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना आवश्यक है।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्षक	विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2907.11 और 2707.60	फिनोल	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका सहित कोई देश	कोई	18.16	प्रति मी. टन	अमेरिकी डॉलर
2.	-वही-	-वही-	उस देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है, के अलावा कोई देश	दक्षिण अफ्रीका	कोई	18.16	प्रति मी. टन	अमेरिकी डॉलर

136. इस उद्देश्य के लिए आयातों का अनुमानित मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित किया जाएगा और सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8 बी, 9, 9 ए के तहत शुल्क को छोड़कर कस्टम शुल्क के लागू स्तर द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

थ. आगे की प्रक्रिया

137. इन जांच परिणामों के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 22nd December, 2020

Case No. SSR-13/2019

Subject : Sunset Review of Anti-Dumping Investigation concerning imports of ‘Phenol’ originating in or exported from South Africa.

A. Background

F. No. 7/25/2019-DGTR.—

1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as ‘the Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as ‘the Rules’) thereof, the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) received an application dated 13th November, 2019 from M/s. Deepak Phenolics Ltd., M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd. and M/s. SI Group India Pvt. Ltd. (hereinafter also referred to as the “Applicants”) requesting for the initiation of a Sunset Review (SSR) investigation of Anti-Dumping Duty (ADD) under the Act and the Rules on imports of ‘Phenol’, (hereinafter also referred to as “Subject Goods” or “Product Under Consideration” or “PUC”) originating in or exported from South Africa (hereinafter referred to as “Subject Country”).
2. The Authority had initiated the original investigation concerning imports of Phenol originating in or exported from European Union (EU), Singapore and South Africa vide Notification No.14/4/2002-DGAD dated 15th February, 2002. The Authority vide Notification No.14/4/2002-DGAD dated 24th June, 2002 notified the Preliminary Findings recommending provisional ADD. The Final Findings were issued by the Authority vide Notification No.14/4/2002-DGAD dated 13th February, 2003, recommending imposition of definitive duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from EU, Singapore and South Africa. Definitive ADD were imposed by the Department of Revenue vide Notification No.47/2003-Customs dated 24th March, 2003.
3. A Mid-Term Review (MTR) investigation was conducted and the Final Findings were notified by the Authority vide Notification No.15/4/2006-DGAD dated 13th July, 2007 recommending continuation of definitive ADD, on all imports of subject goods originating from EU, Singapore and South Africa with a change in the form of duty by imposing a fixed amount of duty. The Department of Revenue imposed the definitive ADD on the subject goods vide Notification No.98/2007-Customs dated 31st August, 2007.
4. The first SSR investigation was initiated on 10th August, 2007. The Final Findings were issued by the Authority vide Notification No.15/9/2007-DGAD dated 4th August, 2008 recommending continuation of the same ADD on the imports of subject goods from EU and Singapore and revised definitive ADD on imports of subject goods from South Africa. On the basis of the recommendations made by the Authority, definitive ADD were imposed by the Department of Revenue vide Notification No.114/2008-Customs dated 31st October, 2008.
5. The second MTR was initiated by the Authority vide Notification No. 15/16/2011- DGAD dated 8th December, 2011 in respect of imports of Phenol originating in or exported from EU, Singapore and South Africa. The Final Findings in the second MTR investigation were notified by the Authority vide Notification No.15/16/2011-DGAD dated 6th February, 2013, recommending continuation of ADD with respect to imports from South Africa and recommending withdrawal of duties on imports of subject goods from EU and Singapore. On the basis of recommendations made by the Authority the Department of Revenue continued the imposition of ADD on imports of subject goods from South Africa and withdrew ADD from EU and Singapore vide Notification No.10/2013-Customs (ADD) dated 3rd May, 2013.

6. In the second SSR investigation, the Authority thereafter recommended continuation of definitive ADD on the subject goods originating in or exported from the subject country vide Notification No.15/21/2013-DGAD dated 27th April, 2015 and the same was extended vide Notification No. 32/2015-Customs (ADD) dated 10th July, 2015 for a period of five years and further vide Notification No. 18/2020-Customs (ADD) dated 9th July, 2020, the current duties were extended up to 9th January, 2021.
7. In terms of Section 9A (5) of the Act, ADD imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Further, Rule 23 (1B) of the Rules provides as follows:

“any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”
8. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the DI, as to whether the expiry of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
9. The Applicants jointly filed an application dated 13th November, 2019 requesting initiation of SSR of ADD imposed earlier and seeking continuation of ADD against imports of Phenol from South Africa. The request was based on the grounds that the expiry of the measure was likely to result in continuation of dumping of the subject goods and consequent injury to the Domestic Industry.
10. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the Domestic Industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated the SSR investigation vide Notification no. 7/25/2019-DGTR dated 27th December, 2019 to review the need for continued imposition of ADD in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of the said ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.
11. The scope of the present review covers all aspects of the Final Findings Notification No.15/21/2013-DGAD dated 27th April, 2015 which had recommended the imposition of ADD on imports of subject goods originating in or exported from the subject country.

B. Procedure

12. The procedure described herein below has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Authority vide Notification No. 7/25/2019-DGTR dated 27th December, 2019 published a public notice in the Gazette of India, extraordinary, initiating anti-dumping investigation against imports of the subject goods from the subject country.
 - ii. A copy of the Notification dated 27th December, 2019 was forwarded by the Authority to all known exporters of the subject goods, the Government of the subject country through its Embassy in India, and other interested parties about the initiation of the subject investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, and to the Government of the subject country, through its embassy, and to other interested parties who made a request in writing in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.
 - iv. The Embassy of South Africa, New Delhi, made legal submissions in response to the initiation notification.
 - v. The Authority forwarded a copy of the Notification dated 27th December, 2019 initiating anti-

dumping investigation to the known producers / exporters in the subject country, and other interested parties and provided them an opportunity to file responses to questionnaires in the form and manner prescribed within time limit as prescribed in the initiation notification or extended time limit, and make their views known in writing in accordance with the Rule 6(4) of the Rules. Copies of the letter and the questionnaire sent to the exporters were also sent to the Embassy of the subject country along with a list of known exporters/ producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject country to respond within the prescribed time.

- vi. The Authority, upon requests made by the interested parties, granted an extension of time to the interested parties to file their response as well as submissions. Vide communication dated 3rd February, 2020, the time was extended up to 22nd February, 2020.
- vii. The Authority forwarded a copy of the Notification to the following known producer/ exporter:
 - a. M/s. Merisol RSA (PTY) Ltd, 2 Sturdee Ave, Rosebank, Sandton, 2196, South Africa.
- viii. In response to the initiation of the subject investigation, M/s. Sasol South Africa (PTY) Ltd., responded seeking time for filing questionnaire response and making submissions. However, no questionnaire response was filed by the exporter.
- ix. The Authority forwarded a copy of the Notification to the following known importers/ users of subject Goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. M/s. Acron Enterprises;
 - b. M/s. Bleach Marketing Pvt. Ltd.;
 - c. M/s. C.J. Shah and Company;
 - d. M/s. Centrum Metalics Pvt. Ltd.;
 - e. M/s. Farmson Pharmaceutical Gujarat Ltd.;
 - f. M/s. Haresh Kumar & Co.;
 - g. M/s. High Polymer Labs Ltd.;
 - h. M/s. India Glycols Ltd.;
 - i. M/s. Kailash Polymers;
 - j. M/s. Kantilal Manilal & Co. Pvt. Ltd.;
 - k. M/s. Karmen International (P) Ltd.;
 - l. M/s. Khetan Brothers;
 - m. M/s. Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.;
 - n. M/s. Kundan Rice Mills Ltd.;
 - o. M/s. Meghdev Enterprises;
 - p. M/s. Naiknavare Chemicals Limited;
 - q. M/s. National Plywood Industries Ltd.;
 - r. M/s. NGP Industries Ltd.;
 - s. M/s. Paras Dyes & Chemicals;
 - t. M/s. PCL Oil & Industries;
 - u. M/s. Rainbow Colours & Chemicals;
 - v. M/s. Resins & Plastic Ltd.;
 - w. M/s. Satguru International;
 - x. M/s. Sonkamal Enterprises;
 - y. M/s. Shubham Dyes & Chemicals Limited;
 - z. M/s. Singh Plasticisers and Resins (I) Pvt.;

- aa. M/s. Torrent Pharmaceuticals Limited;
- bb. M/s. United Phosphorus Ltd.;
- cc. M/s. Wonder Laminates Pvt. Ltd.;
- x. In response to the above, M/s. Agarwal Chemicals, an importer/user, filed a questionnaire response and made submissions.
- xi. The following parties have registered as interested parties/filed legal submissions in response to the initiation notification:
 - a. M/s. Cent Ply;
 - b. M/s. Eximcorp India Private Limited;
 - c. M/s. Atul Ltd.;
 - d. Federation of Indian Plywood and Panel Industry;
 - e. Indian Laminate Manufacturers Association.
- xii. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April to 30th September, 2019 (6 months) and the injury investigation period is from 1st April, 2016 to 31st March, 2017; 1st April, 2017 to 31st March, 2018; 1st April, 2018 to 31st March, 2019, and POI.
- xiii. Transaction-wise imports data for the POI and the preceding three years were procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Directorate General of Systems and Data Management (DGS). The Authority has, relied upon data of DGCI&S and DGS data for calculating the volume and value of imports of the subject goods in India.
- xiv. Further information was sought from the Applicants and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by Domestic Industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- xv. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xvi. The Authority has examined the information furnished by the Domestic Industry to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price (NIP) of the subject goods in India so as to ascertain if ADD lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xvii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 18th May, 2020. Further, a second oral hearing was held on 14th August, 2020 in view of change in the Designated Authority, in pursuance of the decision of the Hon'ble Supreme Court in the matter of *Automotive Tyres Manufacturers' Association vs. Designated Authority*. The parties, who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xviii. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this final finding.
- xix. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this Final Findings, to the extent possible and verified the data/documents submitted by the Domestic Industry to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- xx. The information provided by interested parties on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of

the information filed on confidential basis.

- xxi. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded the final finding on the basis of available facts.
- xxii. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 23rd November, 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings.
- xxiii. *** in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.
- xxiv. The average exchange rate of US\$1 = Rs.70.73/- prevailing during the POI has been adopted by the Authority.

C. Scope of Product Under Consideration (PUC) and Like Article

C.1 Submissions by the Domestic Industry

- 13. The Domestic Industry has made the following submissions with regard to the scope of the PUC and like article:
 - i. The product under consideration in the present petition is Phenol.
 - ii. The PUC was defined by the Authority in its Final Findings dated 27th April, 2015. Since the present investigation is a sunset review investigation, the PUC remains the same as defined in the previously conducted investigation. Further, no significant developments have taken place over the period. Therefore, the Applicants have referred to and relied upon the previous investigation with regard to the PUC.
 - iii. Further, the present Application is for SSR investigation for continued imposition of ADD. The issue of like article has been examined by the Authority in the original investigation as well. Therefore, the Applicants have submitted that product imported from subject country is like article to product produced by the Domestic Industry.

C.2 Submissions by other interested parties

- 14. No submissions have been made by the exporters/other interested parties with regard to the PUC and like article.

C.3 Examination by the Authority

- 15. The PUC in the original investigation, previous SSRs, as well as in the present SSR, is Phenol. In the previous investigation, the PUC was defined as under:

“The product under consideration is Phenol originating in or exported from Singapore, South Africa and European Union. Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms- bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide, etc. This product is classified under Customs Tariff heading no. 2907.11 and 2707.60 as per Indian Trade Classification. The Customs and ITC HS classifications are, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.”

- 16. Rule 2(d) relating to the definition of “like article” specifies that “like article” means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation, or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the article under investigation.

17. From the above definition of the term “like article”, it is noted that the like article has to be identical or alike in all respects to the article under investigation. The scope of the term like article shall also include those articles having closely resembling characteristics to those under investigation in the absence of articles identical or alike in all respects.
18. On the basis of information on record, the Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the Domestic Industry and those imported from the subject country. The two are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, distribution & marketing, and tariff classifications of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers also use the two interchangeably. In view of the same, the Authority holds that the product manufactured by the Applicant constitutes like article to the subject goods being imported into India from the subject country.
19. None of the importers, consumers, exporters, Domestic Industry and other interested parties have raised any objection with regard to the scope of the PUC and like article. In view of the above, information filed by various interested parties and information on record, the scope of the PUC in the present review investigation remains the same as that in the original investigation.

D. Domestic Industry and Standing

D.1 Submissions by the Domestic Industry

20. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to standing and scope of the Domestic Industry:
 - i. The production of subject goods of Applicants, namely, M/s. Deepak Phenolics Ltd., M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd. and M/s. SI Group India Pvt. Ltd., constitute 100% of the domestic production for the subject goods in India.
 - ii. The Applicants are neither related to any exporters in the subject country nor importers of the subject goods in India.
 - iii. Imports made by SI Group are under duty-free scheme and the quantity is insignificant in relation to production and demand in India.
 - iv. The Domestic Industry has alleged dumping during the POI from South Africa and, therefore, only imports from South Africa during the POI is relevant.

D.2 Submissions by other interested parties

21. The other interested parties have made following submissions with regard to the standing and scope of the Domestic Industry:
 - i. M/s. SI Group India Pvt. Ltd cannot be considered as Domestic Industry due to subject goods imported during the POI. The same can be as high as 50% of the imports from South Africa. Therefore, if imports are significant, then M/s. SI Group should be excluded.
 - ii. Three domestic producers provided answers with respect to subject country only and did not provide any answer for imports from other countries. Whereas as per the application proforma, the declaration of imports is required to be provided by the Domestic Industry, specifically for the POI and for the previous three years for all countries including the subject country without fail.
 - iii. M/s. Deepak Phenolics Ltd. is neither an established producer nor was it a part of the ‘domestic industry’ in the original investigation. M/s. Deepak Phenolics Ltd. falls within the category where injury is assessed with respect to causing ‘material retardation to the establishment of an industry in India’. The Rules do not permit combining an ‘established’ Domestic Industry with a Domestic Industry, which is affected by ‘material retardation’ that limits its establishment.
 - iv. Since M/s. Deepak Phenolics Ltd. is not present in the entire injury period, the assessment is flawed and not uniform in nature. The performance is affected owing to scaling issues in newly commenced operations and start-up costs, which are also required to be adjusted.

D.3 Examination by the Authority

22. Rule 2 (b) of the Rules defines Domestic Industry as under:

"(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

23. The present SSR application has been filed by M/s. SI Group India Pvt. Ltd, M/s. Hindustan Organics Chemical Limited and M/s. Deepak Phenolics Ltd. There are no other producers of the PUC in India and the applicants constitute 100% of the total domestic production in India.

24. The Applicants have stated that they are not related to exporters or importers of the subject goods. Further, there are no imports of alleged dumped article from South Africa by M/s. Hindustan Organics Chemical Limited and M/s. Deepak Phenolics Ltd of the product in India.

25. It is noted that the imports made by M/s. SI Group India Pvt. Ltd. during the POI are quite low in absolute volume (650 MT) and in relation to the company's production (3.5%), total imports (0.8%), total India production (3.9%) and demand (0.3%). Moreover, the imports were made under the duty-free scheme. The Authority, therefore, holds M/s. SI Group India Pvt. Ltd. to be an eligible Domestic Industry within the meaning of Rules 2(b) of the AD Rules.

26. As regards the contention of other interested parties that M/s. Deepak Phenolics Ltd. is not an established producer as it has been affected by material retardation, the Authority notes that M/s. Deepak Phenolics Ltd. had commenced its commercial production in November, 2018 and has already achieved 96% capacity utilisation and, therefore, established itself as a leading producer of subject goods in India. The Authority also holds that the scope of the Domestic Industry is required to be established with regard to (a) the investigation period, and (b) production of like article by eligible domestic producers during such period. The Authority, therefore, holds that M/s. Deepak Phenolics Ltd. is one of the constituents of Domestic Industry.

27. In view of the above, the Authority holds that the Applicants are an eligible Domestic Industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

E. Issues relating to Confidentiality**E.1 Submissions by the Domestic Industry**

28. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to confidentiality:

- i. The Domestic Industry has provided all information with strict adherence to the Authority's Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018. Company-wise details and details of imports made by the Applicants is a business proprietary information, which is not amenable to summarization.
- ii. The Authority's Trade Notice No. 7/2018 dated 15th March, 2018 mandates only hard copy of the DGCI&S data to be accessible to the interested parties only after providing declaration/undertaking to the Investigating Officer.
- iii. Evidence of ocean freight adjustment has been provided in the Application. As regards other adjustments, the same has been done as per the established practice of the Authority.
- iv. Information with regard to volume parameters has been provided in the non-confidential version with strict adherence to the Trade Notice 10/2018 dated 7th September, 2018, applicable for two producers, given that the Domestic Industry consisted of two producers during the injury period up to November, 2018.
- v. Purchase policy, sales policy, accounting policy, cost accounting policy, quality control procedure and tests are business proprietary information and not amenable to summarization.

E.2. Submissions by other interested parties

29. The following submissions have been made by other interested parties in this regard:
- i. The soft copy excel file of sorted DGCI&S has not been provided by the Domestic Industry.
 - ii. Company-wise information and details of imports by M/s. SI Group India Pvt. Ltd. have also been claimed confidential by the DI.
 - iii. Annual Reports have not been provided by the Applicants. Only links to website have been shared.
 - iv. Volume figures and profitability in percentage have been claimed confidential by the Applicants.
 - v. Excessive confidentiality has been claimed in violation of Anti-Dumping Agreement and the Rules. Only summarized data has been provided for economic parameters such as capacity, production, capacity utilisation and sales. There is a stark difference from the previous investigations on the same product.
 - vi. Even the purchase policy, sales policy, accounting policy, cost accounting policy, quality control procedure and tests have been treated as confidential.

E.3 Examination by the Authority

30. Various submissions made by the Applicant as well as other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, have been examined.
31. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
32. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:
- “Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
- (2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*
33. As regards the contentions with regard to confidentiality of information, it is noted that information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of Domestic Industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.
34. As regards disclosure of DGCI&S data, the Authority’s Trade Notice No. 7/2018 dated 15th March, 2018, prescribes the procedure for collecting DGCI&S data for Domestic Industry as well as for other interested parties. The interested parties, thus, had access to procure DGCI&S data as per the Trade Notice and defend their interests.

F. Miscellaneous Submissions**F.1. Submissions by the Domestic Industry**

35. The following miscellaneous submissions have been made by the Domestic Industry:

- i. None of the exporters have responded to the questionnaire issued by the Authority. Exporters should, therefore, be considered non-cooperative as per Rule 6(8) and the Authority should proceed according to the best information available.
- ii. None of the interested parties have filed any submissions within the time limit prescribed.
- iii. M/s. Agrawal Chemicals is not an importer of the article being subject to investigation for being dumped in India, as they have not imported the PUC from South Africa.
- iv. Federation of Indian Plywood and Panel Industry is non-cooperative as none of the users under the Association have filed any questionnaire responses. Moreover, the Association itself has not filed any submissions in the permissible time limits.
- v. M/s. Cent Ply has not filed response to prescribed questionnaire issued by the Authority. The party has only filed submissions opposing the interested parties. The party should be considered as non-cooperative in the current investigation.
- vi. M/s. Sasol Limited cannot be considered as an interested party as they have neither registered themselves with the Authority within the timelines prescribed nor filed any questionnaire response as mandated by the Trade Notice No. 11/2018 dated 10th September, 2018.
- vii. The South African producer attempted to justify its non-cooperation under the garb of corona virus. The investigation was initiated in December, 2019, much before the corona virus problem started in South Africa. The Government of South Africa did not declare any lockdown until 25th March, 2020.
- viii. Additional two weeks' time was granted to the interested parties to file the questionnaire response. The Domestic Industry fails to understand the difficulty of the responding exporter to file the questionnaire despite additional time provided.
- ix. COVID-19 cannot be an excuse to allow dumping of the PUC.
- x. The transactions, wherever bulk is mentioned, have been considered as bulk. In the import transactions where bulk is not mentioned, the same is segregated between bulk and packed as per the volumes. If the volume is more than 100 MT, the same is considered as bulk. During the POI only one transaction of 110 kg has been excluded due to abnormal price. The quantity is too small to impact price effect or tantamount to zeroing.
- xi. The period for which duty has been in force is no relevant consideration to determine whether ADD is required to be extended further. The only relevant consideration are the conditions specified under Section 9A(5).
- xii. The Authority has continued the duties for a period beyond 10 years for the reason that there was likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of duties. Facts of the present case are totally opposite from the cases referred to by the interested parties.
- xiii. The POI considered by the Authority is appropriate due to the facts and circumstances of the case. Import prices of the PUC declined significantly during the POI with no commensurate decline in raw material prices.
- xiv. With the imposition of ADD by China, there has been a very drastic decline in the prices.

F.2 Submissions by other interested parties

36. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:

- i. The POI is generally of 12 months. No exceptional circumstances exist to consider a POI of 6 month. It is for the first time an SSR investigation is being carried out with a POI of 6 months. The Domestic Industry has cherry-picked and proposed a shorter 6-month POI in order to

demonstrate injury as a result of reduced profitability in the first two quarters of 2019-20. Phenol is a derivative of crude-petro and natural gas and should not be handled with the same yardstick as applicable to other industrial products. Phenol sales are impacted by frequent fluctuations in costs and selling prices on a daily basis. Hence, for an accurate and objective assessment, a period of at least 12 months is essential and a 6-month POI is extremely inadequate. The Trade Notice No.02/2017 dated 12th December, 2017 has been violated, as it mandates POI to be at least 1 year.

- ii. The imposition of ADD on Phenol in China is not an exceptional circumstance. South Africa was not a subject country, nor does it have high exports to China. Only provisional duties were imposed by China before September, 2019. Provisional duties have no meaning unless final duties are imposed. Imports were only affected for 4 months in the POI due to provisional duties. The same is not enough to justify exceptional circumstances for POI.
- iii. The decline in import prices is only due to fluctuation in raw material pricing.
- iv. The Authority has rightly held previously that ADD beyond 10 years be imposed in special cases only. No special circumstances exist for continuation of ADD.
- v. Since the imports are under duty free schemes, ADD are not required to be extended in the present case.
- vi. Medium, Small and Micro Enterprises (MSMEs) contribute over 50% to GDP and two-thirds of formal employment. They form the biggest user base of Phenol in India. MSMEs shall be gravely affected by such continuation of ADD. The levy of ADD shall be counterproductive as it will hinder growth. COVID-19 has already ravaged all economies around the world and anti-dumping measures during a global recession is not called for.
- vii. Not providing an extension to file the Questionnaire Response is arbitrary and unjustified. It ought to have been granted as per the general practice of the Authority, especially since Sasol is the sole producer-exporter from South Africa.
- viii. Considering the COVID-19 outbreak which started in December, 2019, the abilities of parties to provide information was severely circumscribed.
- ix. The sorting of bulk and packed imports is arbitrary. When transaction cannot be sorted into bulk or packed, such transactions may not be used for price analysis. Further, the Domestic Industry has excluded the high price transactions from South Africa by stating that these are abnormal. The Authority is requested to consider these import transactions.
- x. The higher priced units have been excluded considering them abnormal. Such acts tantamount to zeroing, which is not permissible.
- xi. Sasol is clearly an 'interested party' for the purposes of the present investigation and has an inalienable statutory right to participate in the hearing and present its views to the Authority, regardless of whether it has filed a Questionnaire Response.

F.3 Examination by the Authority

37. The Authority has noted all the arguments and counterarguments of the interested parties and has examined all aspects of the submissions made.
38. With regard to the submissions of the Domestic Industry regarding eligibility of the importer, M/s Agarwal Chemicals as an interested party, the Authority notes that Rule 2(c) provides as under:

“(c) “Interested party” includes -

(i) an exporter or a foreign producer or the importer of an article subject to investigation for being dumped in India, or a trader or business association a majority of the members of which are producers, exporters or importers of such an article;

(ii) the government of the exporting country; and

(iii) a producer of the like article in India or a trade and business association a majority of the members of which produce the like article in India”

39. As submitted by M/s Agarwal Chemical in the Importer Questionnaire Response on record with the Authority, the importer has not made any imports of the PUC from the subject country. Therefore, the party is not an importer of the subject goods from the subject country. However, the party has imported the product from other countries. The Authority has considered submissions made by the company considering that the company has imported the product, though from different sources.
40. Regarding the selection of 6 months as POI, the Authority notes that the adoption of 6 months as POI is not inconsistent with the Rules and is a requirement of the case. The Domestic Industry substantiated the need for considering 6 months as the POI by providing reasons that the import prices have drastically declined during this period. The Applicants submitted that the purpose of fixation of an investigation period is to fix a period to determine whether the product was exported at dumping price and whether the same caused injury. The Authority accepted the POI proposed by the applicant, being satisfied with the reasons given by the Domestic Industry. Further, since the present investigation is an SSR investigation, the Authority has also considered information for the post-POI period (October, 2019 to March, 2020).
41. The time limit for submission of Questionnaire Response was mentioned in the initiation Notification, and the Authority had granted an extension of two weeks. Keeping in view the pressing timelines, a further extension was not granted.
42. With regard to submissions on eligibility of M/s. Sasol South Africa (PTY) Ltd., Federation of Indian Plywood and Panel Industry and M/s. Cent Ply, the Authority has, on the basis of facts and circumstances of the case, and the practice of the Authority, acknowledged and accepted the submissions made by the interested parties.
43. The argument that imports made under advance licence should be excluded from the total imports was examined. An Advance licence/authorization holder has a choice either to import the inputs on a duty-free basis or procure the same from indigenous sources by using the mechanism of Advance Release Order. The purpose of injury analysis is to examine and capture the effect of dumped imports on the Domestic Industry. Therefore, it would not be reasonable to exclude the duty-free imports from the injury analysis. It would not be appropriate to consider that imports made under advance licences do not cause injury to the Domestic Industry.
44. The Authority notes that DGCI&S data indicates that all imports of the PUC from the subject country were in bulk form.
45. Only abnormally priced PUCs have not been included for the purpose of analysis.

G. Normal Value, Export Price and Dumping Margin

G.1. Submissions by the Domestic Industry

46. The submissions made by the Domestic Industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
- i. The Domestic Industry has claimed normal value in South Africa based on its export price to Belgium as it is the second largest export destination of South Africa.
 - ii. The export price is adjusted on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight and port expenses to arrive at net export price.
 - iii. The dumping margin calculated is not only significant, but also substantial.
 - iv. There is a preferential sequence for determining normal value. The Supreme Court has also held so in the matter of Ministry of Commerce vs. M/s. Haldor Topsoe. If acceptable material is available with regard to the comparable price in the ordinary course of trade in the exporting country itself, then the normal value will have to be determined on that basis.
 - v. The South African Revenue Service (SARS) is the revenue service (tax-collecting agency) of the South African government. The opposing interested party has neither established as to why SARS statistics is not appropriate nor provided any alternative method for normal value calculation. The opposing interested parties is questioning the data of the subject country Government without any basis.

G.2 Submissions by other interested parties

47. The submissions made by other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
- i. The construction of Normal Value on the basis of exports to Belgium is not permissible and is highly inflated. As per practice, due to non-cooperation of exporter, Domestic Industry's cost should be used for Normal Value. The reasoning that Belgium is the second largest market after India and, therefore, it is appropriate is random. One should examine how Belgium is appropriate for comparing with South Africa. Third country prices can be relied upon only in a situation when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade or otherwise. There are no claims from the Domestic Industry that such a situation exists. An appropriate third country has to be determined on the same criterion as for the purpose of determining an appropriate market economy third country as per Annexure I Para 7.
 - ii. There is no merit in calculation of dumping margin based on Domestic Industry's costs as Sasol's process and raw materials are extremely different and dissimilar from that of the Domestic Industry.
 - iii. For lack of legally sustainable normal value, the application should be rejected. If normal value is unsustainable, dumping margin is also unsustainable.
 - iv. ITC calculations based on SARS statistics cannot be used as neither the point of sale, nor the terms thereof can be ascertained.
 - v. For Ocean freight, World Freight Rates LLC data has no sanctity and is not tenable as it has not been sourced from a public authority and thereby, cannot constitute judicially noticeable facts.
 - vi. No evidences have been provided for Normal value and Export Price adjustments. Claims regarding freight, marine insurance, Commission and Inland Transportation are abnormally high and are unsubstantiated by any evidence.
 - vii. Since the price of Phenol fluctuates on a daily basis and market-to-market, there cannot be a concept of normal value of NIP.

G.3 Examination by the Authority

48. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:
- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*
 - (b) *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*
49. The Authority sent questionnaires to the known exporter from the subject country advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, the exporter from subject country has not cooperated in this investigation by filing their Questionnaires' responses.

Normal Value

50. As none of the producers/exporters from subject country have responded and none of the interested parties have provided any evidences of domestic prices of like article in the subject country, the Authority has determined the normal value for all producers/exporters on the basis of best available information in accordance with Rule 6 (8) by adopting export price from South Africa to Belgium as normal value. Belgium is the second largest export destination for South Africa; first being India; and constitutes more than 5% of the exports to India. The normal value determined is mentioned in the dumping margin table.

Export Price

51. As none of the producers/exporters have cooperated, the Authority has adopted the DGCI&S import data for determining the CIF price. The ex-factory export price has been determined after considering adjustments on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight and port expenses as per facts available. Accordingly, the ex-factory export price is calculated and mentioned in the dumping table.

Determination of dumping margin for producers and exporters in the subject country

52. Considering the normal value and export price as above, the dumping margins for all producers/exporters of the subject goods from the subject country is determined as below. It is seen that the dumping margin is significant.

Dumping Margin Table

Normal Value	USD/MT	***
Export Price	USD/MT	***
Dumping Margin	USD/MT	***
	%	***
	Range	80-100

H. Assessment of Injury and Causal link**H.1 Submissions by the Domestic Industry**

53. The submissions of the Domestic Industry with regard to injury and causal link are reproduced below:
- The demand for the subject goods has increased over the injury period in India.
 - The imports have continued despite imposition of ADD. In absolute terms, the imports remain significant and at almost similar levels through the injury period, with a minor decline in the POI.
 - The imports have increased (by about 50%) in post-POI.
 - The share of the subject country in total imports has almost doubled over the injury period. The imports in relation to consumption have increased during post-POI.
 - The imports are undercutting the prices of the Domestic Industry and are depressing the prices of Domestic Industry in the market.
 - Imports are significantly underselling the prices of the Domestic Industry. The injury margin is positive during the POI and post-POI.
 - The selling price of the Domestic Industry has declined significantly over the injury period and the same is not due to the decline in raw material prices. The selling price has declined more than the decline in cost, thus, resulting in price depression.
 - The Domestic Industry is unable to earn profits due to the presence of dumped products in India. The losses have further increased during post-POI.

- ix. The capacity of the Domestic Industry has increased during the POI since M/s. Deepak Phenolics Ltd. commenced its production during the period. Consequently, the sales and production of the Domestic Industry have also increased.
- x. With new capacities in India, the market share of the Domestic Industry has increased over the injury period. The market share of the imports from subject country has also increased during post-POI.
- xi. Inventories with the Domestic Industry have been significant throughout and have increased significantly in the POI.
- xii. The return on investment has severely declined in the POI and further declined during post-POI.
- xiii. The quarter-wise analysis shows further deterioration in the performance of the Domestic Industry. The losses have increased in each quarter of the POI and post-POI.
- xiv. The fact that the consumption in India is higher than the capacities with the Indian producers may justify imports per se. The same, however, does not justify dumping.
- xv. NIP is required to be calculated for the POI. The POI in the present case was not affected by COVID-19 and, therefore, the argument should not be accepted.
- xvi. It is an established position in law that all forms of injury can co-exist in a case. The Domestic Industry has referred to the case *TRINSEO EUROPE GmbH Versus Union of India*.
- xvii. It is very presumptuous of the opposing interested parties to assume that the situation of the Domestic Industry has not undergone a change since 2016-17. Even public statements of M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd. will show that it is no more a sick unit.

H.2 Submissions by other interested parties

54. The other interested parties have submitted as under:

- i. Imports are inevitable as Domestic Industry is unable to meet the entire demand in India. The Domestic Industry can only meet 70% of Demand.
- ii. Due to COVID-19, raw material prices have gone to an all-time low, NIP maybe calculated accordingly again with due adjustments.
- iii. The volume parameters have significantly improved and imports of 15,000 MT from South Africa has no effect on them.
- iv. There is no price undercutting and no price suppression or depression in the present investigation and, therefore, no price effect is present.
- v. The interpretation of WTO jurisprudence by Domestic Industry is flawed and zeroing is not permissible. The Panel has only mentioned about the examination of the number of sales at undercutting prices and the extent of undercutting of such sales and has not laid down any other form of examination.
- vi. The cost of sales declined over the injury period but the selling price increased and, therefore, imports have no price effect.
- vii. All profitability parameters have significantly improved over the injury period and, therefore, there is no injury to the DI.
- viii. The mere existence of positive price undercutting, injury margin per se does not imply that the Domestic Industry has suffered injury.
- ix. The margin of price undercutting has significantly declined over the injury period indicating price undercutting of lesser frequency and margin.
- x. The domestic sales of the Domestic Industry have increased from 13% to 60% of the total demand in the POI. Therefore, imports from subject country have no effect.
- xi. Indicators such as capacity addition by the Domestic Industry, along with no price suppression, depression or undercutting, an increase in sales quantity, show no injury.

- xii. M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd.'s current position should be re-examined keeping in view the findings of the Authority. Similarly, DGTR held, M/s. SI Group India Pvt. Ltd. was operating at full capacity and their performance was found to be not affected by imports from various countries.
- xiii. There has been no change in circumstances since the previous findings have been provided. For M/s. Deepak Phenolics Ltd., the Applicants should have explained why their alleged injury shall not be attributed to factors other than dumped imports. Maybe the new entrant is making profits and old players are into losses due to with depreciated plant and machinery. Moreover, injury is determined for DI as of whole and not individual constituents of the Domestic Industry.
- xiv. The profit of Phenol Acetone plant of Deepak Phenolics does not show any injury to the Domestic Industry. Deepak Phenolics commissioned their Phenol plant in November, 2018 and has more than 72% of India's installed capacity. The other two manufacturers - Hindustan Organic Chemicals and SI group have very small capacity plants and such small plants without backward integration into Benzene and Propylene cannot be competitive. Thus, injury, if any, to the two small players cannot be attributed to imports. Deepak Phenolics has been able to operate the plant at close to 100% capacity in such a short period. The very healthy profitability and high capacity utilisation shows that there is no injury to Deepak Phenolics.
- xv. The Domestic Industry mentioned that the demand in the country is more than the installed capacity by 88,000 MT per year. They estimate that 1,00,000 MT of Phenol demand in India is for manufacture of products, which are exported and, thus, should be excluded from the demand-supply gap as these imports can be made under advance licence where no duty will be applied. What is the source of information showing 1,00,000 MT of Phenol used for manufacture of export products? It is in the interest of the nation that we use local raw materials for both local and export demand of the finished goods to the maximum extent possible and there is no merit in reducing the local demand by 1,00,000 MT as argued by the Domestic Industry. Thus, there is a clear gap between Indian demand and supply of Phenol.
- xvi. The Authority cannot disregard its own trade notice and no sympathetic or special concession can be accorded to any party.
- xvii. Price underselling cannot be considered as a factor for the purpose of assessing whether the Domestic Industry is suffering from material injury and the same has to be considered only for the purposes of quantifying the amount of ADD to be levied. The price underselling is an irrelevant factor as far as determining material injury is concerned.
- xviii. It is not appropriate to look at the decline in import prices on a standalone basis. It should be examined in the light of decline in costs.
- xix. Trade remedial measures on Phenol have continued since 1999. If ADD has failed to arrest the injury, clearly there are factors other than alleged dumping contributing to injury.
- xx. If the injuries are arising from or are attributable to global recession affecting prices, it is also a factor other than dumping.
- xxi. There is a co-product generated during the production of Phenol for which the market size in India is insufficient. The Applicants are not able to dispose of the co-product at remunerative prices. The inability to dispose of the co-product is a critical factor causing injury to the applicants. This should also be examined in detail before any decision is taken by the Authority.

H.3 Examination by the Authority

- 55. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of all the interested parties with regard to injury to the Domestic Industry. The injury analysis so made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
- 56. Rule 11 of the Rules read with its Annexure – II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, “... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles”.

57. As regards the consequent impact of dumped imports on the Domestic Industry, Para (iv) of Annexure II of the Rules states as under-
- "(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."*
58. The Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the Domestic Industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.
59. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the Domestic Industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the Domestic Industry.
60. While considering the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the Domestic Industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the Rules. The Authority has taken note of various submissions of the Domestic Industry and the exporters / importers / traders / users on injury to the Domestic Industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.
61. With reference to the argument of demand-supply gap, the Authority considers that possible demand-supply gap may not be a reason for depriving a Domestic Industry from seeking redressal against dumped imports causing injury.
62. As regards the argument that NIP should be determined on the basis of current raw material prices which are very low due to COVID-19 situation, the Authority notes that it is consistent practice of the Authority to determine NIP for the POI, and in the instant case also NIP has been determined accordingly.
63. With reference to the argument of low volume of imports from South Africa, it is noted that the volume of imports from the subject country has increased in POI.
64. As regards the argument of long period of duty, the Authority notes that the law clearly envisages that the ADD can be extended further from time to time, if it is found that dumping and consequent injury to the Domestic Industry is likely to recur in the event of cessation of ADD. The Authority recommends anti-dumping duty only after following the requirements prescribed under the laws.

65. As regards the argument that price underselling is not a parameter for injury analysis, it is noted that the law does not provide for an exhaustive list of parameters which can be examined for injury analysis. Further, price underselling is nothing but injury margin for the country as a whole and it is a consistent practice of the Authority to examine the same.
66. As regards the argument that M/s. Deepak Phenolics Ltd. is earning huge profits in Acetone and Phenol business, the Authority notes that injury to the Domestic Industry is required to be analysed for the product concerned and not for the sector as a whole. The injury to the Domestic Industry has been analysed for Phenol based on available data/information.
67. Further, it may not be necessary that all parameters of injury show deterioration. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether the Domestic Industry has suffered injury or not. The Authority has examined the injury parameters taking into account the facts and submissions made by the Domestic Industry as under:

I. ASSESSMENT OF DEMAND

68. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of the Domestic Industry and other Indian producers have been added to the total imports into India and the same have been summarized below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
Domestic Industry's Sales	MT	42,604	53,129	1,31,185	1,22,462	2,44,924
Trend	Indexed	100	125	308	287	575
Imports from South Africa	MT	15,534	17,638	18,314	9,679	19,359
Trend	Indexed	100	114	118	62	125
Imports attracting ADD	MT	83,101	87,637	38,085	11,200	22,400
Trend	Indexed	100	105	46	13	27
Imports from Other Countries	MT	1,83,239	1,82,812	1,72,570	55,901	1,11,801
Trend	Indexed	100	100	94	31	61
Total Demand	MT	3,24,477	3,41,215	3,60,154	1,99,242	3,98,484
Trend	Indexed	100	105	111	61	123

69. It is noted that the demand for the PUC has increased consistently over the injury period, and in the POI.

VOLUME EFFECTS OF DUMPED IMPORTS

i. Import volumes and market share of imports

70. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. In the present case, however, ADD has been in force. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject goods from the subject country and the share of the dumped imports during the injury investigation period have been analyzed below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
South Africa	MT	15,534	17,638	18,314	9,679	19,359
Trend	Indexed	100	114	118	62	125
Countries Attracting ADD	MT	83,101	87,637	38,085	11,200	22,400
Trend	Indexed	100	105	46	13	27
EU	MT	4,213	15,825	4,410	3,076	6,152
Trend	Indexed	100	376	105	73	146
Korea	MT	54,768	53,557	25,802	2,840	5,680
Trend	Indexed	100	98	47	5	10

Singapore	MT	24,120	18,254	7,873	5,284	10,568
Trend	Indexed	100	76	33	22	44
Others	MT	1,83,239	1,82,812	1,72,570	55,901	1,11,801
Trend	Indexed	100	100	94	31	61
Grand Total	MT	2,81,874	2,88,087	2,28,970	76,780	1,53,560
Subject Imports in relation to						
Total imports	%	6%	6%	8%	13%	13%
Trend	Indexed	100	111	145	229	229
Indian Production	MT	36%	33%	13%	8%	8%
Trend	Indexed	100	92	37	21	21
Indian Demand	%	5%	5%	5%	5%	5%
Trend	Indexed	100	108	106	101	101

71. It is seen that:

- Imports from the subject country has increased throughout the injury period, including in the POI.
- The share of imports from the subject country in total imports has increased in the POI, as compared to the preceding years.
- Imports from the subject country in relation to Indian production have declined over the injury period with new capacities established in India. Imports from the subject country in relation to demand has remained the same during the investigation period.

PRICE EFFECT OF DUMPED IMPORTS

72. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization and NIP of the Domestic Industry have been compared with the landed cost of imports from the subject country.

i. Price undercutting

73. In order to determine whether the imports are undercutting the prices, the Authority has undertaken comparison between the landed price of the product and the average selling price of the Domestic Industry net of all rebates and taxes. The landed price of imports, domestic prices and margin of undercutting are shown as per the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	122	94	94
Landed Price	Rs/MT	55,588	63,645	88,795	75,131	75,131
Trend	Indexed	100	114	160	135	135
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	40-60	40-60	0-20	0-20	0-20

74. It is seen that landed price of imports is below the net sales realization of the Domestic Industry, showing positive price undercutting.

ii. Price suppression or depression

75. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority has examined the changes in the landed price of imports, and costs & prices of the Domestic Industry over the injury period, when ADD was in force.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	117	101	101
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	122	94	94
Landed price	Rs./MT	55,588	63,645	88,795	75,131	75,131
Trend	Indexed	100	114	160	135	135

76. It is seen that whereas the selling price of the Domestic Industry and landed price of imports increased till 2018-19, the same declined thereafter. The cost of sales increased till 2018-19 and then declined. It is also noted while the landed price of the imports was below the cost of sales throughout the injury period, except in 2018-19.
77. It is noted from above that imports from the subject country have depressed the prices of the Domestic Industry. The Domestic Industry has also suffered price suppression on account of imports of subject goods from the subject country.

iii. Price underselling

78. The price underselling has been evaluated by comparing the NIP with the landed price of the subject imports.

Particulars	Unit	South Africa
Landed Value	Rs./MT	75,131
Non-Injurious Price	Rs./MT	***
Price underselling	Rs./MT	***
Price underselling	%	***
Price underselling	Range	0-10

79. From a comparison of the landed price with the NIP, it is noted that the price underselling is positive.

Impact on Economic Parameters relating to Domestic Industry

80. Annexure – II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Various injury parameters relating to the Domestic Industry are discussed herein below.

i. Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

81. The performance of the Domestic Industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
Capacity Per annum	MT	76,750	76,750	1,600,83	1,38,375	2,76,750
Trend	Indexed	100	100	209	361	361
Production	MT	43,524	53,490	1,38,431	1,26,634	2,53,268
Trend	Indexed	100	123	318	582	582
Capacity Utilization	%	57	70	86	92	92
Trend	Indexed	100	123	152	161	161
Domestic Sales	MT	42,604	53,129	1,31,185	1,22,462	2,44,924
Trend	Indexed	100	125	308	575	575

All trends are on an annualised basis.

82. The Authority notes the following:

- The capacity with the Domestic Industry increased during the injury period with the commencement of commercial production by M/s. Deepak Phenolics Ltd. in 2018-19.
- The production and sales have increased over the injury period. Resultantly, the capacity utilization of the Domestic Industry improved over the injury period.

ii. Market share in demand

83. The market share of alleged dumped imports and the Domestic Industry have been examined as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
Domestic Industry	%	13.1	15.6	36.4	61.5	61.5
Trend	Indexed	100	119	277	468	468
Subject Country	%	4.8	5.2	5.1	4.9	4.9
Trend	Indexed	100	108	106	101	101
Countries attracting ADD	%	25.6	25.7	10.6	5.6	5.6
Trend	Indexed	100	100	41	22	22
Other countries	%	56.5	53.6	47.9	28.1	28.1
Trend	Indexed	100	95	85	50	50

84. It is seen that the market share of the Domestic Industry increased over the injury period, with the addition in capacity. Further, the share of imports from the subject country in demand has remained almost same over the injury period.

iii. Inventories

85. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
Average Inventory	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	301	591	591
Inventory as No. of days of Production	Days	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	95	102	102
Inventory as No. of days of Sales	Days	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	98	102	102

All trends are on an annualised basis.

86. It is seen that there is a significant increase in the level of inventories in 2018-19 and in the POI due to the increase in production and sales.

Profit or Loss, Cash Profits and Return on Investment

87. The performance of the Domestic Industry with regard to profit, return on investment and cash flow is as follows.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	117	101	101
Selling price	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	122	94	94
Profit per unit	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	71	163	15	15
Total Profit/(Loss)	₹ Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	647	118	118
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	668	315	315
PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	376	242	242
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	80	52	18	18

All trends are on an annualised basis.

88. It is noted that the profit per unit declined from the base year till 2017-18, thereafter increased in 2018-19 and then declined significantly in the POI. The Return on Investment declined significantly in the POI.

iv. Employment, wages and productivity

89. The details of employment and wages are given below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
No. of Employees	Nos.	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	197	197	197
Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	171	120	240
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	318	582	582

All trends are on an annualised basis.

90. It is seen that performance of the Domestic Industry has improved in respect of employment, wages and productivity in the POI.

v. Growth

91. The summarized position regarding growth is as under -

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	POI
Production	Y/Y	23	159	83
Domestic Sales	Y/Y	25	147	87
Capacity Utilisation	Y/Y	23	24	(8)
Average Inventory	Y/Y	10	174	96
Market share of Domestic Industry	Y/Y	19	134	69
Profit/Loss	Y/Y	(10)	615	(82)
Cash Profit	Y/Y	(12)	659	(53)
PBIT	Y/Y	(3)	289	(36)
Return on Capital Employed	Y/Y	(20)	(35)	(66)

92. It is noted that while volume parameters of the Domestic Industry have shown a growth over the period. As noted above, the volume parameter has witnessed a positive growth due to the addition in capacities by the Domestic Industry.

vi. Margin of dumping

93. It is found that the margin of dumping is positive. There is continued dumping of subject goods from the subject country.

vii. Factors affecting prices

94. It is noted that the landed value of the subject goods from subject country is not only below its net selling price but also below the NIP of the Domestic Industry. Further, the landed prices of subject imports have depressed the prices of the Domestic Industry leading to a significant decline in profitability during the POI. The imports of subject goods from third countries are either attracting ADD or at de-minimis levels or are at higher prices. Dumped imports are impacting the prices of the product in the market.

viii. Ability to raise capital investments

95. Significant investment was recently made in the PUC. The Domestic Industry is suffering a significant decline in profitability during the POI. With the competition being faced by the Domestic Industry because of the dumped imports, the operations of the industry have been impacted which has affected its ability to raise capital investment. The Domestic Industry is a multi-product company and, therefore, the ability to raise capital investment is not governed based on the performance of the product alone.

I. Magnitude of Injury Margin

96. The Authority has determined NIP for the Domestic Industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilisation of the raw materials by the Domestic Industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. The production in the POI has been calculated considering the best capacity utilisation and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed. The NIP of the Domestic Industry has been determined and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The analysis shows that during the POI, the landed value of subject imports from the subject country was below the NIP of the Domestic Industry, as can be seen from the table below, demonstrating positive injury margin.

Particulars	Unit	South Africa
Landed Value	US\$/MT	1062.22
Non-Injurious Price	US\$/MT	***
Injury Margin	US\$/MT	***
	%	***
	Range	0-10

Overall Assessment of injury

97. The examination of imports of the subject goods and the performance of the Domestic Industry shows the following:
- The volume of imports from the subject country has increased in absolute terms and in relation to total imports.
 - The imports from the subject country are undercutting the prices of the Domestic Industry and the price underselling is also positive.
 - Imports from the subject country have depressed the prices of the Domestic Industry. The Domestic Industry has also suffered price suppression on account of imports of subject goods from subject country.
 - Production, sales and capacity utilization have increased over the injury period.
 - The performance of the Domestic Industry has significantly deteriorated in respect of profitability, and return on capital employed.

J. Causal Link & Non Attribution Analysis

98. Under Section 9A (5), the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties irrespective of whether there have been any imports of the PUC during the review investigation period or not. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry:

i. Volume and Prices of Imports from Third Countries

99. It is seen that the imports into from third countries are either attracting ADD or are under ADD investigation or at higher prices. Therefore, the imports of third countries have not caused injury to the Domestic Industry.

ii. Contraction in Demand

100. It is seen that the demand of the PUC has increased over the injury period. Therefore, contraction in demand cannot be considered as a reason of injury to the Domestic Industry.

iii. Export Performance of the Domestic Industry

101. The Domestic Industry has exported the PUC in negligible volumes. A possible deterioration in the export performance of the Domestic Industry is, therefore, not a possible cause of injury to the Domestic Industry.

iv. Developments in Technology

102. It is noted that the technology and the production process for producing the PUC have not undergone any significant development. The possible development in technology is not a cause of injury to the Domestic Industry.

v. Performance of other products of the company

103. The performance of other products being produced and sold by the Applicants is not a possible cause of injury to the Domestic Industry. The Applicants consider that information relating to the PUC is the only relevant information for the present purpose and the Applicants have provided this information as the Domestic Industry.

vi. Conditions of Competition and Trade Restrictive Practices

104. The investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the Domestic Industry.

vii. Changes in the patterns of consumption

105. There have been no material change in the pattern of consumption of the PUC. Changes in the pattern of consumption have not caused claimed injury to the Domestic Industry. In fact, the demand for the subject goods has increased over the relevant period.

K. Analysis of Continuation of Injury and Causal Link**L. Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping and Injury**

106. The Authority observes that this is an SSR investigation and the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if ADD were to be allowed to expire, even if there is no current injury.

L.1 Submissions by the Domestic Industry

107. The Domestic Industry submitted as follows with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury –

- i. Dumping margin determined in all previous investigations relating to the PUC have been positive.
- ii. Significant imports in the presence of ADD show likelihood of increased imports in the event of cessation of ADD.
- iii. Excess production capacities held by the producer in subject country are significant. The producer has a capacity of 40,000 MT with no matching demand in the domestic market.
- iv. Freely disposable capacities with the foreign producer show likelihood of increased imports in the event of cessation of duty. Due to low domestic demand, the producer has an approximate freely disposable capacity of about 36,800 MT.
- v. The exporter in the subject country has significant unutilized capacities.
- vi. Export orientation of the producer in the subject country is very high at about 75% of their capacity.
- vii. The producer is pre-dominantly export-oriented, and the Indian market is important to their interests. About 65-70% of the total exports are made to Indian market.
- viii. Producers are habitual of dumping, as can be seen from the price difference in respect of exports to various markets.
- ix. Overcapacity in Asian Countries, self-sufficiency of Chinese industry have led to oversupply of Phenol in the market. This has significantly changed the market scenarios.
- x. There is a shifting pattern of trade in Phenol, whereby the source of the imports into India changes in tandem with the imposition and cessation of ADD.
- xi. Phenol is present in excess quantities in the markets globally as there is an over-supply of the product.
- xii. India is a lucrative market for the exporters from subject country, and no other market offers such prospects, as the Indian market. Prices at which the PUC is exporter is exporting to the other markets is lower than India.
- xiii. There is an increase in non-essential imports in the presence of increased domestic capacities in India.
- xiv. The export price from South Africa to India was consistently lower than the export price to the rest of the world. Despite low export price to India and ADD in existence, India still has remained historically the major export destination for South Africa.
- xv. The Domestic Industry has a right to sell in the market and the same cannot be taken away by dumped imports.
- xvi. The Authority has considered injury margin as a basis of likelihood. In the instant case the injury margin is positive in the POI, which clearly establishes likelihood in the event of cessation of ADD.

- xvii. At present the world is faced with over capacity with an exception of India. Therefore, India has become the most desirable market for all the exporters of Phenol.
- xviii. Sluggish demand in Asia will result in other exporting countries to export aggressively to India. India being the major export destination for South Africa, it will have no choice but to reduce its prices further in order to sustain in Indian market.

L.2 Submissions by other interested parties

108. The following submissions have been made by other interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury:

- i. South Africa only caters to a small demand in India under advance licence and the exports are not attractive as other countries have higher prices.
- ii. Submissions on essential and non-essential imports are irrelevant. Domestic Industry acts as if they have a right to sell in market all of its capacity regardless of competition.
- iii. Domestic Industry has failed to provide any evidence in support of their case on the likelihood of dumping and injury.
- iv. There is no excess or unutilized capacity in South Africa, and the imports under duty free schemes are bound to take place as Domestic Industry cannot cater entire demand. Import from other sources will also continue.
- v. There would be no surge in imports on expiry of ADD as imports from South Africa are stable and have remained constant throughout.
- vi. Existence or the threat of recurrence of both dumping and injury are required so as to continue the ADD.
- vii. For likelihood, historical dumping margin has been significant for the reason that the dumping margin was determined on the basis of facts available.
- viii. India is a price sensitive market as well as the largest market for South African exports and therefore, economies of scale permit lower pricing. Therefore, prices are lower than exports to other countries.
- ix. The capacity of South Africa is at 40,000 MT, which is equivalent to only 10% of India's demand for the PUC. The unutilized capacities are only 6,000 MT which constitutes a negligible quantity in relation to the demand in India which stands at 3,80,000 MT. Freely disposable capacity claims are misleading.
- x. China and Thailand are not export markets of South Africa, and, therefore, expansion in these countries is irrelevant.
- xi. A shifting pattern of trade is irrelevant as imports from South Africa have remained consistent despite the existence of ADD on them for the past 18 years.
- xii. South Africa does not export the PUC to China and secondly, because the countries upon which China has imposed ADD do not include South Africa. Therefore, Chinese industry has no relevance.
- xiii. South Africa is not going to be affected by any alleged sluggish demand in Asia as the same is not its major market. Moreover, the evidence pertains to 2013.
- xiv. Since per unit realization is the lowest in India, it cannot be lucrative market for South Africa.
- xv. Notion of non-essential import is unsustainable in law. South Africa cannot be expected to divert all its production to India and lose other lucrative markets to fulfil the demand for essential imports into India.
- xvi. The argument of the Domestic Industry that the level of capacity utilisation of foreign producers is quite low is contradicted by the Domestic Industry's own data which shows that capacity utilization in South Africa is quite high at 80%.

L.3 Examination by the Authority

109. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the Domestic Industry and other interested parties, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.

110. The Authority has used data of actual imports, as available from DGCI&S, and has not made any distinction between essential and non-essential imports, as claimed by the Domestic Industry.

111. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure – II (vii) of the Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties. The present investigation is a sunset review of ADD earlier imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of ADD is warranted. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration viz.:

- i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
- ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
- iv. Inventories of the article being investigated.

i. Continued & existing dumping and injury

112. The Authority notes that the imports of the PUC from the subject countries has been increasing in the injury period, including the POI and further in the post-POI period. Further, the dumping margin is positive. It is also seen that these imports are undercutting the Domestic Industry's prices and are at a price below NIP of the Domestic Industry. Dumping is likely to continue in the event of cessation of ADD.

ii. Surplus capacities in subject country

113. The Authority, on the basis of submissions made by the interested parties and evidence on record, has summarized the information as under –

Particulars	South Africa
Capacity	40,000
Production	34,000
Domestic demand	4,000
Surplus Capacities	36,000

114. It is seen that a large portion of the capacity with the exporters is surplus. The domestic demand can cater to only 10% of the capacity created by the company.

115. It is seen that the exporter has unutilized capacities to the extent of 15% of its capacities.

Particulars	Quantity (MT)
Capacity	40,000
Production	34,000
Unutilized capacities	6,000

116. On the basis of information on record, the Authority notes that the exporter has significant freely disposable capacity, which can be diverted to India in the event of cessation of ADD.

Particulars	Unit	2015	2016	2017	2018
Capacity	MT	40,000	40,000	40,000	40,000
Production	MT	34,000	34,000	35,000	34,000
Unutilized capacities	MT	6,000	6,000	5,000	6,000
Exports	MT	23,227	32,253	34,898	30,818
Freely Disposable Capacity	MT	29,227	38,253	39,898	36,818

iii. Price Undercutting and Attractiveness of India as a Market

117. It is noted that price undercutting is positive during the POI, and thus, cessation of ADD currently in place is likely to lead to intensified dumping causing injury in the form of low volume of sales, reduced selling price and decline in profits to the Domestic Industry.
118. The Authority is required to establish that the price prevailing in the domestic market i.e. India is attractive for the exporter to divert the quantity exported to the third countries. It is noted that the landed value of imports is below the net selling price of the Domestic Industry in the POI.
119. It is seen that 91% of production and 77% of capacity of the exporter was destined for exports in the POI due to the low domestic demand in the country. The exporter is largely producing the goods for export.

Particulars	Quantity (MT)
Capacity	40,000
Production	34,000
Exports	30,818
Export Orientation	
as a % of Production	91%
as a % of Capacity	77%

120. The statement of exports of PUC from the subject country, as available on Trademap, is as follows:

Export destinations	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
India	18,475	19,376	18,368	11,830	23,660
Belgium	-	1,585	350	3,034	6,068
Brazil	3,269	4,394	2,634	1,004	2,009
Taipei, Chinese	1,788	2,075	1,722	842	1,684
Argentina	338	753	696	529	1,059
New Zealand	1,093	1,218	1,280	463	927
Egypt	-	80	583	256	512
Korea	100	1,220	560	120	241
United Kingdom	4,644	2,157	3,573	110	220
Others	2,546	2,039	1,053	301	603
Total	32,253	34,898	30,818	18,491	36,982

121. It is seen that India is historically a major export destination for the subject country despite ADD in force. The exports to India constitute 64% of the total exports of Phenol from South Africa. Further 59% of the total Phenol capacity and 70% of total Phenol production in South Africa is being exported to India. From Trademap, it is further observed that the export price of the subject goods from South Africa to India has consistently remained one of the lowest, when compared to the export prices at which South Africa exported to third countries in 2019.

Conclusion on Likelihood of Dumping and Injury

122. The evidence on record shows that the volume of dumped imports from subject countries has increased in absolute terms throughout the injury period including the POI. The imports from the subject country are undercutting the prices of the domestic industry and the price underselling is positive. The imports from the subject countries are suppressing and depressing the prices of the domestic industry. The performance of the Domestic Industry has significantly deteriorated during the POI. The Domestic Industry has suffered continued injury during the present period. It is seen that there is a clear likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry. The dumping margin and injury margin from the subject country continue to be positive during the successive reviews including the present sunset review. It is also noted that none of the producer and exporter from subject country has cooperated during the present investigations. The information on record shows that the exporters have surplus production capacities, unutilized capacities and freely disposable capacities that are likely to be diverted to India in the event of cessation of the anti-dumping duty. The evidence on record also shows that the exporters from subject country are highly export-oriented and are largely producing the goods for export. Further, the Authority also notes that the export price of the goods from South Africa to India has consistently remained the lowest, when compared with export prices to third countries. India has been a major export destination for the subject country. Thus, all these parameters indicate that, in the event of cessation of the existing ADD, the exporters in the subject countries are likely to intensify exports of the dumped products in India at dumped prices, leading to recurrence of injury to the domestic industry.

M. POST DISCLOSURE COMMENTS

123. Post-disclosure submissions have been received from the interested parties. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties including reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

M.1 Submissions by the Domestic Industry

124. The submissions made by the domestic industry are as follows:

- i. Agarwal Chemical cannot be considered as an importer in the present investigation as the company has not imported phenol from South Africa.
- ii. Sasol South Africa (PTY) Ltd. cannot be considered as an interested party in the present investigation as it has not registered itself as an interested party nor filed questionnaire responses.
- iii. Federation of Indian Plywood and Panel Industry has to be considered as non-cooperative as they failed to file any comments or information related to their users within time limit and none of their members have filed questionnaire responses.
- iv. Century Ply should be considered non-cooperative as they have not filed any questionnaire responses.
- v. The margin of dumping from the subject country is positive. There is continued dumping of the subject goods from the subject country.
- vi. The volume of imports has increased in absolute terms when compared to base year.
- vii. The price undercutting and underselling are positive. Further, the import prices are suppressing and depressing the prices of the Domestic Industry.
- viii. The performance of the Domestic Industry has deteriorated in respect of profitability and ROCE.
- ix. The Domestic Industry has suffered continued injury. No other known factors other than dumped imports are causing injury to the Domestic Industry.
- x. There is likelihood of dumping and injury to the Domestic Industry in the event of cessation of ADD.
- xi. Producers are habitual of dumping, as can be seen from the price difference in respect of exports to various markets.

- xii. Overcapacity in Asian countries, self-sufficiency of Chinese industry have led to oversupply of Phenol in the market. This has significantly changed the market scenarios.
- xiii. There is a shifting pattern of trade in Phenol, whereby the source of the imports into India changes in tandem with the imposition and cessation of ADD.
- xiv. There is increase in non-essential imports in presence of increased domestic capacities in India.
- xv. The domestic industry submitted that Formats B and D working and the NIP should be sufficiently disclosed.
- xvi. Considering the low volume of imports from subject country in the POI, the consistent increase in imports from subject country throughout the injury period and the significant increase in imports from subject country post-POI, the same duty is required to be extended.
- xvii. The Authority is requested to continue ADD in the same form and in terms of USD.

M.2 Submissions by other interested parties

125. The submissions of other interested parties on the Disclosure Statement are reproduced herein below:

- i. In the disclosure statement, the fact of declaration of imports for M/s Hindustan Organics Chemical Ltd. and M/s Deepak Phenolics has been recorded only for subject country i.e. South Africa and no declaration for other countries has been made/received from these two producers. Further, the details of the imports made by M/s SI Group India Pvt. Ltd. are also from the subject country i.e. South Africa and no details or analysis of imports made by SI Group India Pvt. Ltd. from other countries has been carried out.
- ii. In the disclosure statement, even the period of declaration of imports by M/s Hindustan Organics Chemical Ltd. and M/s Deepak Phenolics Ltd. has not been specified.
- iii. As per the application proforma, the declaration of imports is required to be provided by the Domestic Industry specifically for the POI and for the previous 3 years for all countries, including the subject country without fail. The analysis of imports by the domestic producers is required to be made not only with respect to POI but also for the previous years.
- iv. The only reason in support of consideration of 6 months POI in this investigation recorded in the Disclosure Statement is the drastic decline in import prices, which by no means can be regarded as being exceptional or rare situation.
- v. The logic of not considering a 12-month POI and then considering a 6-month POI, along with a 6-month post-POI information is not clear. The Authority has no discretion to allow a POI less than 6 months in an Application for SSR as the word 'should' in the Trade Notice 02/2017 indicates a mandatory obligation to adopt a POI of at least one year. Reference has been made to UOI v. Kumho Petrochemicals where the Supreme Court held that 'may' cannot be read as 'shall'. Further, reference was made to Forech India v. Designated Authority where the Delhi High Court held that the DA cannot disregard its own trade notice and no sympathetic or special concession can be accorded to any party.
- vi. The Authority may indicate the basis of concluding that all imports of the PUC from the subject country were in bulk form, also the basis of classifying certain transactions as abnormal and exclusion of high priced imports.
- vii. The determination of dumping margin for the subject country on the basis of the constructed normal value on the basis of export prices by South Africa to a third country i.e. Belgium is a clear departure from the consistent practice of the Hon'ble DGTR.
- viii. There is no continuation or current injury to the domestic industry.
- ix. Prices of exports from South Africa to third countries derived on the basis of ITC calculations based on SARS statistics cannot be relied upon as neither the point of sale nor the terms thereof can be ascertained. The prices mentioned in such statistics are always based on certain assumptions and presumptions and cannot form the basis to arrive at even a tentative normal value for the country.

- x. The import volumes of the subject goods from South Africa disclosed in the Disclosure Statement are significantly at variance as compared to the import data disclosed by the domestic industry in their application/written submissions.
- xi. The figures for demand, indices for cost of sales and for selling prices and the landed value are different in the Application and in the Disclosure Statement.
- xii. The landed values have increased by 60% in 2018-19 as compared to base year i.e. 2016-17 whereas the domestic selling prices could increase only by 22%. There are no reasons/analysis of this scenario in the Disclosure Statement as to why the domestic industry could not increase its prices to the level of 60% increase in the landed values.
- xiii. The profit and ROCE of the Domestic Industry declined in the POI as a result of the plant of Deepak Phenolics getting fully operational due to high production cost of Deepak Phenolics and not otherwise.
- xiv. The figures of cash profit for POI(A) appears to be wrong as the same has not been annualized.
- xv. The correct way to analyze inventories is to examine the same as percentage of sales or number of days of inventories and the analysis of inventories on any other basis would lead to misleading and incorrect conclusions.
- xvi. With regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the Disclosure Statement in paras 112 to 121, it is submitted that there is a reproduction of the submissions of the Domestic Industry and the same have been accepted without analyzing them objectively.
- xvii. There has been an excessively prolonged period for which ADD have been imposed on imports of the subject goods from South Africa. Imports of the subject goods from South Africa have been levied with definitive ADD since 2003.
- xviii. The Applicants have clearly contravened the provisions for confidentiality under the rules in the following instances:
 - a. Actual Capacity of Domestic Industry in MT;
 - b. Actual Production of Domestic Industry in MT;
 - c. Sales volumes of Domestic Industry in MT; and
 - d. Market share and demand in %
- xix. There is clearly no adverse impact on the volume parameters of the Domestic Industry. The data provided in the Application clearly denotes the absence of any price effect on the Domestic Industry.
- xx. There has been no expansion in capacities in South Africa and the volume of imports from South Africa has remained consistently low, bearing an overall declining trend.
- xxi. South Africa has unutilized capacity of only about 6,000 MT and the same is merely 1%-2% of total demand in India which is not at all significant and even if, for the sake of argument, it is assumed that the said unutilized capacity would be exported to India after withdrawal of duties, it will not have any impact on the Indian market.
- xxii. In the present factual matrix, the facts clearly establish that there is no causal nexus between the alleged injury or likelihood of injury and the continued imports of the subject goods from South Africa.
- xxiii. The POI in the Anti-dumping investigation regarding imports of Phenol from Thailand and USA and the injury period in the present investigation overlap. From the Authority's examination in the Preliminary Findings of the former, clearly, the performance of HOCL has been proven to be affected by several other factors and the injury to the Domestic Industry is held to be not attributable to the alleged dumping of the subject goods. Therefore, the findings concerning a break in the causal link in the case of *Phenol from Japan and Thailand* are *ex facie* applicable to the present investigation. It is an established fact that the injury to HOCL is self-inflicted, based on factors that are not attributable to the imports from South Africa. Hence, the claim for the injury to the domestic industry being attributable to imports from South Africa is liable to be dismissed.

- xxiv. The parameters provided in the Application make it absolutely clear that the Applicants do not suffer any injury on account of the imports and the injury if any is clearly not attributable to imports from South Africa.
- xxv. The basis of adjustments of 5% for freight, commission and port expenses furnished by DI has not been substantiated and is not credible. DA has not disclosed quantum of adjustments made for arriving at ex-factory export price from CIF value and is bound to disclose as it is not confidential information. Export price calculated by Applicant has been exaggerated and the Authority has to re-determine the same.
- xxvi. The Authority seems to have calculated normal value entirely on the basis of information furnished by Applicants, and therefore, the adjustments adopted must be disclosed and no confidentiality can be claimed by the Applicant too.
- xxvii. Normal value for non-cooperating producers, exporters and country cannot be confidential as it is not business sensitive or proprietary information. Reference has been made to UOI v. Meghmani Organics Ltd. where it was observed that DA cannot treat any information confidential unless such claim has been made.
- xxviii. The capacity in the subject country is not even sufficient to fulfill even 40% of the demand-supply gap for Phenol in India. Negligible unutilized capacities cannot result in recurrence of injury even when it was utilized for exports to India.
- xxix. The Authority has not examined whether other export markets exist which can absorb additional production by the producer/exporters which possess surplus capacities.
- xxx. 22% ROCE not to be applied. Such benchmark to not be followed since it was made at a time when the PLR was 18%. The AD Agreement mandates actual cost and not notional cost.
- xxxi. Imposition of ADD for long duration increases cost to end consumer. User industries will suffer irreparable damage in case duties are continued.

M.3 Examination by the Authority

- 126. With regard to the issues raised by the domestic industry regarding the status of the interested parties, the Authority has duly examined the same and recorded its findings in the relevant paragraphs of this final finding.
- 127. With regard to the issues raised by parties relating to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority has duly examined the relevant parameters and has recorded its findings in the relevant paragraphs of the present final findings. The issues related to the standing of the Domestic Industry, PUC, confidentiality, Normal Value, Export Price and the POI raised by the other interested parties have already been dealt with in the relevant paragraphs above. The Authority notes that the POI in the present investigation has been considered as per the established practice which is consistent with the AD Rules.
- 128. As regards the argument of appropriateness of Belgium for normal value determination, it is noted that since none of the exporters from subject country has responded and since none of the interested parties have provided any contrary evidence for normal value, the Authority has relied upon facts available ie export price from subject country to Belgium for determination of normal value. Further Belgium is the second largest export destination for South Africa; first being India; and constitutes more than 5% of the exports to India.
- 129. As regards changes in data in the Application and the Disclosure Statement, it is noted that in the Application the Domestic Industry had considered the import data of only 29071110. Later it was found that the subject goods are imported under the HS code 29071190 also. The imports in the Disclosure Statement includes imports of subject goods under Customs Tariff heading no. 29071110 and 29071190 and accordingly, the imports and other relevant parameters have been revised.
- 130. As regards the duration for which ADD has been in force, the Authority notes that the duration of duty is irrelevant under Section 9A (5). The Authority is required to examine likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the Domestic Industry.

N. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

131. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
132. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

O. CONCLUSION

133. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- There is continued dumping of the subject goods from subject country and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty.
 - The performance of the domestic industry has deteriorated and remains vulnerable due to dumping of the subject goods.
 - The information on record shows likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury in case the Anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage.

P. RECOMMENDATIONS

134. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, causal link, and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that extension of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends the extension of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.
135. Under these circumstances, it is considered appropriate to recommend continuation of definitive anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from the subject country as per the dumping and injury margins calculated for the current investigation period, for a further period of 5 years from the date of its imposition. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends continuation of definitive anti-dumping duties equal to the lesser of margins of dumping and margins of injury so established, so as to remove the injury to the domestic industry, in the form and manner described in the table below. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of definitive antidumping duty as modified, on all imports of the subject goods from the subject country as per column 7 in the duty table below, for a further period of five years.

Duty Table

SN	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2907.11 and 2707.60	Phenol	South Africa	Any country including South Africa	Any	18.16	Per MT	US\$
2	-do-	-do-	Any country other than country attracting anti-dumping duty	South Africa	Any	18.16	Per MT	US\$

136. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Q. FURTHER PROCEDURE

137. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the with the relevant provisions of the Act.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority